● वर्ष-3
● अंक-158
रायपुर, शनिवार
10 फरवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› काजल खरीदते समय इन...

बजट 2024-25 @ विकसित छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट: विष्णु देव साय

रायपुर। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा आज वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया। नवगठित सरकार द्वारा अमृतकाल के रूप में प्रस्तुत किया गया यह पहला बजट हैकेनीव का बजट . बजट गरीब , युवा , अन्नदाता और नारी (ज्ञान) की समृद्धि और पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरना विकास को प्रोत्साहित करने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बजट मोदी की गारंटी के तहत वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमृतकाल में एक विकसित राज्य के रूप में उभरने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए 1 नवंबर 2024 तक अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @2047 तैयार किया जाएगा । इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने में हमारी मदद करने वाला पहला मध्यावधि लक्ष्य अगले 5 वर्षों में हमारे राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से दोगुना करके वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य होगा।

मजदूरों और आदिवासियों के समग्र विकास द्वारा आर्थिक स्थिति को विकसित करने की गहन जिम्मेदारी की भावना के साथ यह बजट पेश किया गया है ।

हमने बनाया है , हम ही सवारेंगे, हमने 10 मौलिक रणनीतिक स्तंभों का मसौदा तैयार किया है जो 2047 तक हमारे मध्यावधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करेंगे।

छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा और दशा संवारने वाला बजट

बजट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट आने वाले कई वर्षों तक छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा और दशा संवारने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट में कर का कोई नया प्रस्ताव नहीं है, न ही मौजूदा करों की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है। यह बजट सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाला और विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। अमृतकाल का छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय आज वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करने के बाद समिति कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद और वित्त सचिव श्री अंकित आनंद भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बजट में हमारा फोकस GYAN यानि गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। बजट में सभी वर्गों की चिन्ता की गई है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्युमेंट भी है, जो छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास की परिकल्पना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा।

मुख्यमंत्री ने बजट के प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा करने और बोनस का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपता संग्राहकों के लिए हम चरण पादुका योजना पुन: शुरू करेंगे। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रूपए की वार्षिक सहायता के लिए बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ न हो इसके लिए राज्य सरकार ने पीएससी की अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। बजट में युवाओं के रोजगार के लिए प्रावधान किया गया है। साय ने कहा कि कृषि उन्नति योजना के लिए बजट में 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले प्रदेश के 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों को अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 3000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पांच हॉर्स पॉवर कृषि पंपों के लिए नि:शुल्क बिजली की आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मुख्य बजट में 8369 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके पहले द्वितीय अनुपूरक में 3800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल की बेहतर व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन हेतु पीएचई विभाग के बजट को दोगुना करते हुए 5047 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट केवल पैसे का लेखा-जोखा नहीं, अपितु छत्तीसगढ़ के भविष्य की उन्नति की आधारशीला है। इस बजट में कोई नया कर प्रावधान नहीं किया गया है, न ही किसी कर की दर में वृद्धि का प्रस्ताव है। इसके बावजूद बजट के आकार में बढ़ोत्तरी हुई है। बजट के माध्यम से टेक्नालॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। यह बजट सामाजिक-आर्थिक विकास के हर आयाम को छूने वाला और मोदी जी के गांरटी को पूरा करने वाला बजट है।

मोदी की गारंटी

- छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी के वादों को पूरा करने के लिए समर्पित है
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान। वर्ष 2023-24 द्वितीय अनुपूरक में 3,799 करोड़ रुपये ।
- महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान ।
- कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये इससे 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे ।
- ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रु प्रति मानक बोरा भुगतान
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को गत वर्ष 7000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रदेशवासियों के लिए श्री रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन का प्रावधान ।
- राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास हेतु विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान ।
- इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा।

प्रमुख योजनाएँ

- छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8,369 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान.
- जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- हायर सेकेंडरी स्कूल के विकास और रखरखाव के लिए 3,952 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- 5 एचपी कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान.
- 3,400 करोड़ के लिएमुख्यमंत्री खड्याण ट्टुसहायता योजना रुपये का प्रावधान.
- राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- अमृत मिशन योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री जनमन योजना में राज्यांश के रूप में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- श्री राम लला दर्शन (अयोध्या धाम) के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस क्रमश: प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और संभाग में स्थापित किए जाएंगे।
- रायपुर-भिलाई के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विकसित किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ सेंटर आफ स्मार्ट गवर्नेंस का गठन
- छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन
- बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में इको-पर्यटन और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र विकसित किए जाएंगे।
- नए उद्योगों को नीति में शामिल करने के लिए नई उद्योग नीति तैयार की जाएगी
- ई-वाहनों को प्रोत्साहन , कुसुम योजना को अपनाने आदि के अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए जलवायु कार्य योजना तैयार की जाएगी।
- राज्य की खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना प्राथमिकता दी जाएगी।

विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की रणनीति

- ज्ञान हमारे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु
- तकनीक आधारित रिफार्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास
- तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना
- प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल
- अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नयी संभावनाओं पर जोर
- सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना
- बस्तर-सरगुजा की ओर भी देखो
- डिसेंट्रेलाइज्ड डेवलपमेंट पाकेट्स
- छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास
- क्रियान्वयन का महत्व

प्रमुख समाचार

कृषि से आय वृद्धि

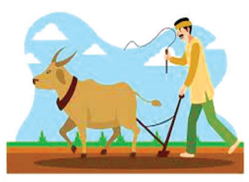

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कृषि एवं सहायक गतिविधियों (उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन) के प्रोत्साहन हेतु समन्वित प्रयास किया जायेगा। कृषि विभाग के बजट में विगत वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल 13 हजार 438 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि उन्नति योजना के क्रियान्वयन के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 08 हजार 500 करोड़ की साख सीमा निर्धारित की गई है। इस राशि पर ब्याज अनुदान के लिए 317 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सिलफिली जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, कुनकुरी जिला जशपुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय तथा खड़गवां जिला मनेन्द्रगढ़.चिरमिरी.भरतपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के गत वर्ष के बजट प्रावधान में 70 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 17 हजार 529 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत सरकार द्वारा 18 लाख से अधिक आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 08 हजार 369 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजन हेतु महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 02 हजार 788 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नवीन सड़कों के निर्माण एवं वर्तमान सड़कों के संधारण हेतु 841 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्व.सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार गतिविधियों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 561 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों एवं कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 19 जिलों के पी.वी.टी.जी. बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क एवं पुल निर्माण हेतु 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सिंचाई

सिंचाई रकबे के विस्तार के लिए नवीन सिंचाई परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। संभावित सिंचाई परियोजनाओं की सूची में 10 करोड़ से अधिक लागत के 156 कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं हेतु 692 करोड़, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ तथा एनीकट एवं स्टॉपडेम निर्माण हेतु 262 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केलो सिंचाई परियोजना की नहरों का काम वर्षों से अधूरा था। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर निर्माण के काम को पूरा किया जायेगा। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन हेतु डिजिटल सूचना प्रणाली विकसित की जायेगी। इसके लिए राज्य जल सूचना केन्द्र की स्थापना हेतु 01 करोड़ 56 लाख का प्रावधान किया गया है। सिंचाई बांधों की देखभाल एवं मरम्मत के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन का पृथक से सेटअप स्वीकृत किया गया है। सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे सिंचाई बांधों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना संभव हो सकेगा।

वाणिज्य एवं उद्योग

वर्तमान उद्योग नीति की समीक्षा करके नई उद्योग नीति जारी की जायेगी। इसमें राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाद, वनोपज एवं खनिज संपदा तथा रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जायेगा और नये उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कोर सेक्टर में पूर्व से कार्यरत उद्योगों को क्षमता विकास के लिए अनुकूल अवसर प्रदान किये जायेंगे। प्रदेश में आर्थिक और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट के क्षेत्रों में उपलब्ध उपयुक्त शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जायेगा। इसकी योजना निर्माण हेतु 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नये औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 60 करोड़, फूड पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़, लागत पूंजी अनुदान हेतु 200 करोड़ एवं ब्याज अनुदान हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जायेगी। इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। इस हेतु 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अत्याधुनिक छत्तीसगढ़ स्टार्ट.अप हब और नॉलेज प्रोसेस आऊट सोर्सिंग इकाईयां स्थापित करने एवं राज्य में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किये जाने हेतु स्टार्ट.अप समिट का आयोजन किया जायेगा।

शिक्षित प्रदेश- विकसित प्रदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 को तत्परता से लागू किया जायेगा। चरणबद्ध रूप से इसका क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश के बच्चों एवं युवाओं को उनकी विशिष्ट योग्यता के अनुरूप विकास के अवसर प्रदान किये जायेंगे। डिजिटल एवं ए.आई. आधारित इको सिस्टम के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षकों की भर्ती एवं पदस्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी, विश्वसनीय एवं सुगम व्यवस्था लागू की जायेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च, इनोवेशन, गुणवत्ता उन्नयन आदि कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ हायर एजूकेशन मिशन का गठन किया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध रीति से छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जायेगी। प्रथम चरण में जशपुर, बस्तर, रायगढ़, कबीरधाम एवं रायपुर में इसी वर्ष से छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्टार्ट.अप, इनोवेशन एवं रिसर्च, को बढ़ावा देने हेतु सेन्ट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फेसिलिटी का उन्नयन किया जायेगा। इस हेतु 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में 20 नवीन शिक्षण विभाग में 33 नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे। इस हेतु 03 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

कहां से मिलेंगी भाजपा को 370 सीटें, इस भरोसे की कितनी हैं संभावनाएं

विजय विद्रोही

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में वह कहा है, जिसे कहने से आमतौर पर प्रधानमंत्री कतराते रहे हैं। शायद यह पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री ने चुनावों की घोषणा से पहले ही अगले पांच साल के एजेंडे को भी सामने रख दिया हो। यह आत्मविश्वास है या अतिआत्मविश्वास या जुमला या फ्लोटिंग वोटर को प्रभावित करने के साथ विरोधियों को पस्त करने की रणनीति है, अथवा यह समान विचारधारा के विरोधियों को ढका-छिपा निमंत्रण है? कहा गया है कि भाजपा को अपने दम पर 370 और एनडीए को कुल मिलाकर 405 सीटें मिलेंगी। क्या वस्तुत: यह संभव है? तकनीकी तौर पर जरूर संभव है। अगर राजीव गांधी के समय कांग्रेस 1984 में चार सौ पार सीटें ला सकती है, तो नरेंद्र मोदी की भाजपा भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? लेकिन दो अंतर देखे जा सकते हैं। 1984 का चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या पर उमड़ी सहानुभूति और गुस्से का इजहार था। इसके अलावा तब कांग्रेस का विस्तार जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक था। भाजपा का विस्तार ऐसा है कि लोकसभा की 543 सीटों में से लगभग 150 सीटें ऐसी हैं, जो

आज तक उसने जीती नहीं हैं। अगर कोई पार्टी 543 में से 390 में ही मौजूद है, तो वह अपने दम पर 370 तक कैसे पहुंच सकती है?

चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि अगर भाजपा का पांच फीसदी वोट बढ़ता है, तो वह अधिकतम 343 तक पहुंच सकती है। भाजपा को 2014 में 31 फीसदी वोट के साथ 282 सीटें मिली थीं। 2019 में भाजपा का वोट छह फीसदी बढ़ा और सीटें 21 बढ़ गईं। अगर भाजपा को 370 तक पहुंचना है, तो छह की जगह आठ-दस फीसदी वोट बढ़ाने होंगे। उसे ज्यादा ऐसी सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, जहां पांच फीसदी से भी कम वोट मिले हैं। इसमें आंध्र प्रदेश की 25 और तमिलनाडु की 39 सीटें आती हैं। केरल में जरूर भाजपा को दहाई संख्या में वोट मिले हैं, पर वह खाता नहीं खोल पाई है। अगर यह मानकर चलें कि भाजपा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब हो जाती है, तो 303 सीटों तक पहुंच सकेगी। अगर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में बढ़त ले ले, तो आंकड़ा सवा तीन सौ तक पहुंचेगा। यानी अगर भाजपा को 370 तक पहुंचना है, तो उसे बंगाल और ओडिशा में भी संख्या बढ़ानी होगी। महाराष्ट्र और बिहार में पिछला प्रदर्शन दोहराना होगा। पिछली बार भले ही भाजपा ने 224 सीटें दो लाख के ज्यादा के अंतर से जीती थीं, पर 77 सीटें ऐसी भी थीं, जिन्हें भाजपा एक लाख या उससे कम के अंतर से जीत पाई थी। इन 77 सीटों पर विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार उतारता है और वोट ट्रांसफर करने पर पूरा जोर लगाता है, तब भाजपा मुश्किल में पड़ सकती है।

चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि अगर विपक्ष एक रहता है और उसके वोट प्रतिशत में पांच फीसदी का इजाफा होता है, तभी भाजपा 303 से घटकर 223 पर सिमट सकती है। स्पष्ट है कि भाजपा की रणनीति अपना कुनबा बढ़ाने के बजाय विपक्षी कुनबे में क्लेश कराने की होगी। क्लेश बढ़ेगा, तो आम वोटर की नजर में विपक्ष की विश्वसनीयता कम होगी। यहां भी निशाने पर कांग्रेस को लिया जा रहा है। साफ है कि भाजपा को लगता है कि क्षेत्रीय दलों के प्रति नरम रुख अपनाया जाए। भाजपा अगर ऐसा कुछ कर रही है, तो कुछ भी नाजायज नहीं कर रही है। चुनाव जीतने के लिए हर तरह के रणनीतिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है।

देखा जाए तो राम मंदिर, राष्ट्रवाद, करोड़ों की संख्या में लाभार्थी, मोदी की छवि के बावजूद भाजपा कोई जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। जो पार्टी मेयर का चुनाव भी पूरी गंभीरता से लड़ती हो, वह लोकसभा चुनाव कितनी संजीदगी से लड़ेगी, इसका अनुमान लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाजपा की लड़ाई विपक्षी दल ही आसान कर रहे हैं। अगर ममता बनर्जी कहें कि कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट जाएगी, अगर स्टालिन तमिलनाडु की 39 सीटों को ध्यान में रखकर सनातन का संकट खड़ा कर उत्तर भारत की 200 सीटों को संकट में डाल दें, अगर केजरीवाल और भगवंत मान दिल्ली, पंजाब की 20 सीटों को नाक का सवाल बनाने पर आमादा हो जाएं, तो इसके लिए मोदी को तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

लोन वर्राटू अभियान के तहत दो नक्सलियों का सरेंडर

■ हिंसा और उत्पीड़न से तंग आकर लिया फैसला

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू से प्रभावित होकर दो नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। एसपी दन्तेवाड़ा गौरव राय और एएसपी रामकुमार बर्मन के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के साथ साथ लोन वर्राटू यानी घर वापस आईये अभियान जिले में चलाया जा रहा है। जिससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली घर वापसी कर रहे हैं। इसी कड़ी में दो नक्सलियों ने घर वापसी की है।सरेंडर करने वाले नक्सलियों के मुताबिक वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं।

सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने बताया कि नक्सली संगठन में उनके साथ शोषण, अत्याचार और बाहरी नक्सली भेदभाव करते थे। नक्सली संगठन अपने ही आदिवासी भाइयों को मारने के लिए प्रेरित करते थे।जिससे तंग आकर दोनों ने मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया और आत्म समर्पण किया है।

एसपी गौरव राय ने कहा आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाली सभी प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 170 ईनामी नक्सलियों सहित कुल 669 नक्सलियों ने सरेंडर किया है।

समर्पित नक्सली इन्द्रावती एरिया कमेटी और

मलांगेर एरिया कमेटी की प्रतिबंधित नक्सली संगठन में काम कर चुके हैं। जिसमें रमेश राणा डीएकेएमएस उपाध्यक्ष हांदावाड़ा स्कूलपारा थाना बारसूर का रहने वाला है। जबकि दूसरा गोण्डेरास पंचायत जीआरडी सदस्य मुचाकी मुया गोण्डेरास नेडीपारा थाना फुलबगड़ी जिला सुकमा का निवासी है। मुचाकी मुया ने आठ फरवरी को पुलिस उप महानिरीक्षक दन्तेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप, एसपी गौरव राय के सामने डीआरजी ऑफिस दन्तेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया।

नक्सलगढ़ पहुंचा बुलडोजर, सरपंच के कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन का एक्शन

नारायणपुर। जिले के करलखा गांव में गुरुवार को प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और सरपंच अधारी राम सलाम के अवैध कब्जे को तोड़ दिया। गांव वालों की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है।

ग्राम पंचायत करलखा में सरपंच अधारी राम सलाम ने पंचायत की 27 डिसमिल जमीन में से 13 डिसीमल जमीन पर कब्जा कर कॉम्प्लेक्स बना दिया था। जिसकी शिकायत गांव के ही लोगोंने ने कलेक्टर से की। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने तहसीलदार को जांच करने को कहा। जांच में तहसीलदार और वन विभाग ने जमीन पर बेचा कब्जा कर भवन निर्माण करना पाया। सरपंच को नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर कब्जा हटाने को कहा गया। लेकिन सरपंच पर नोटिस का कोई असर नहीं पड़ा। गुरुवार को तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम दल बल और बुलडोजर के साख गांव पहुंची और भवन पर बुलडोजर चलवा दिया।

तहसीलदार अविनाश कुजूर ने कहा सरपंच ने सरकारी जमीन पर कब्जा ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स बनाया बल्कि कई पेड़ों की कटाई भी की। सरपंच ने पहाड़ी काटने के साथ ही कई पेड़ों की भी कटाई की। जांच के बाद राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है। इस तरह के अवैध कब्जे पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। शासन का दावा है कि जहां जहां अवैध कब्जे होंगे उसपर बुलडोजर चलाए जाएंगे। गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल में महादेव सट्टा एप मामले में बहस के दौरान विधायक धरमजीत सिंह ने महादेव सट्टा के आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग की थी।

नक्सलियों के स्मारकों पर चला जवानों का बुलडोजर, तीन स्मारक ध्वस्त

बीजापुर। बीजापुर में शुक्रवार को एक बार फिर नक्सलियों के स्मारक पर जवानों का बुलडोजर चला है। बासागुड़ा इलाके में पुलिस जवानों ने नक्सलियों के तीन स्मारकों को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को बासागुड़ा थाना क्षेत्र में जिला बल सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान पर नेंड्रा की ओर निकली थी। इसी दरमियान नेंड्रा में नक्सलियों द्वारा बनाया गया 6, 8 व 12 फीट के तीन स्मारकों को सुरक्षाबल के जवानों ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया।

अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का स्वागत

नारायणपुर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामलला के दर्शन करने देशभर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में नरायाणपुर से भी श्रद्धालुओं का पहला जत्था अयोध्या गया था। जहां रामलला के दर्शन करने के बाद पहला जत्था गुरुवार शाम को नारायणपुर लौटा आया है। इन राम भक्तों का नगर वासियों और सनातन धर्म मंच के सदस्यों ने आरती और तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया।

नारायणपुर जिले से बीते दिनों हिंदू धर्म के विभिन्न संगठनों के 41 सदस्यों का दल अयोध्या पहुंचा और रामलला के दर्शन किये। जिसके बाद श्रद्धालुओं का पहला जत्था गुरुवार शाम को नारायणपुर वापस लौट आया है। पहले जत्थे में नारायणपुर जिले से कुल 41 सदस्य राम मंदिर दर्शन यात्रा में शामिल रहे। जिनके सकुशल लौट आने की खुशी में शहर के हनुमान मंदिर के पास स्वागत सभा का आयोजन किया गया। दर्शन कर लौटे सदस्यों की पैर दुलाकर आरती उतारी गई और तिलक लगा कर आत्मीय स्वागत नगर वासियों ने किया है। इस दौरान रामलला के दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं ने अपने अयोध्या यात्रा का अनुभव साझा किया। श्री राम मंदिर की सुंदरता और अयोध्या नगरी की भव्यता के किस्से उन्होंने लोगों को बताए। अंत में मौजूद सभी लोगों को प्रसाद का वितरण किया गया।

असमंजस में अन्नदाता! अब सरकार ही है सहारा

■ धान भी नहीं बिका, ऊपर से सिर पर 9 करोड़ से ज्यादा का कर्ज

गरियाबंद। झिरिपानी निष्टीगुड़ा समिति के 28 गांव के अलावा डोहल, झराबहाल, धुगियामुड़ा, मूड़ागांव, मूंगझर, सोनामुन्दी, केंदुपाटी और टेमरा के 1818 किसान एक दाना धान नहीं बेच पाए हैं। इन पर इसी खरीफ सीजन का जिला सहकारी बैंक में 9।95 करोड़ का ऋण बकाया है। बैंक के नियम के मुताबिक 15 मार्च तक लोन को चुकाना होता है। ऐसा नहीं किया तो 16 मार्च से लोन की राशि पर ब्याज दंड यानी 12 प्रतिशत ब्याज लगना शुरू हो जाएगा।

अक्टूबर महीने में बैंक ने समिति के माध्यम से नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलते ही कर्जदार किसानो की नींद उड़ी हुई है। किसान लगातार सीएम के समक्ष ज्ञापन सौंपने के साथ ही सड़क में रैली निकालकर अपनी मांगों को अवगत करा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन के हर उस दफ्तर में दस्तक दे रहे हैं। जंहा से उन्हें उम्मीद है। आज भी किसान नेता जय कृष्ण नागेश, असलम मेमन, जदु राम, जगमोहन के नेतृत्व में लगभग 50 कृषक का प्रतिनिधि मंडल, कृषि, तहसील और एसडीएम के समक्ष जाकर अपनी मांगों पर हुई कार्रवाई के बारे में पूछते नजर आए।

कृषक नीलांबर मरकाम, श्याम सुंदर,

शशीधर, शोभाराम ने बताया कि 26 गांव के कृषक एक भी दाना धान नहीं बेच पाए हैं। कर्ज भी पटाने लायक नहीं हैं। फसल क्षतिपूर्ति राशि और बीमा योजना का लाभ 1 मार्च तक नहीं मिला तो उनकी स्थिति अगले सीजन किसानी करने लायक नहीं रहेगी। बैंक में डिफॉल्टर होते ही उन्हें अगले सीजन का ऋण नहीं मिलेगा। पहले से काफी कर्ज है, साहुकारी कर्ज भी बढ़ जाएगा। किसानों ने कहा कि मार्च तक उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आमरण अनशन करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है।

सत्ता बदलते ही कर्ज माफी की आस खत्म हो गई। क्षतिपूर्ति की मामूली रकम से किसानों की भरपाई संभव नहीं है। ऐसे में अब फसल बीमा योजना पर अन्नदाताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। अब तक नुकसान की रिपोर्ट प्रशासन ने जो बनाई है, उस अनुपात में बीमा का क्लेम मिलता है तो किसानों की भरपाई कुछ हद तक हो सकेगी।

जानकारी के मुताबिक निजी बीमा कंपनी अनुबंध के आधार पर लोन की राशि का 6 प्रतिशत यानी ढाई करोड़ से ज्यादा देवभोग तहसील से लेगी। योजना के तहत कृषक अंशदान के रूप में बीमा प्रीमियम का 2 प्रतिशत यानी की 88 लाख का भुगतान कृषकों को दी गई ऋण राशि में हो चुकी है। शेष राशि तय अनुपात में कंपनी राज्य और केंद्र सरकार से लेगी।

तहसीलदार गेंद लाल साहू ने कहा कि पटवारी और आरईओ की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित कृषकों की लिस्टिंग की गई है। जिसमें धान विक्रय करने वालों के नाम विलोपित किए जा रहे हैं। सभी को आरबीसी 6(4) के तहत 8500 रुपये प्रति हेक्टयर के दर पर क्षतिपूर्ति राशि जल्द दी जाएगी। कृषि उपसंचालक चंदन राय ने बताया कि जिला स्तर की सभी प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। बीमा कंपनी ने रिपोर्ट का प्रति परीक्षण भी कर लिया है। प्रीमियम की शेष राशि राज्य से लेने के बाद अब केंद्र से लेने की प्रकिया जारी है। इसके खत्म होते ही तय प्रतिशत के आधार पर बीमा की राशि का भुगतान मार्च के पहले सप्ताह तक होने की पूरी संभावना है।

मनेंद्रगढ़ में ठंड बढ़ी, पड़ रही हाड़ कंपाने वाली सर्दी

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। एमसीबी जिले में एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी है। गुरुवार रात को तापमान 7.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले मंगलवार का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया था। पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आ रही सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तापमान में गिरावट के साथ साथ धुंध भी गहराती जा रही है। पिछले तीन दिन से दिन व रात के तापमान में निरंतर गिरावट आ रही है। खासकर रात का तापमान जमाव बिंदु की ओर बढ़ने लगा है। तापमान में गिरावट के साथ साथ धुंध भी गहराने लगी है। सुबह काफी देर कोहरे के बाद धूप खिल रही है लेकिन शीत लहर की वजह से धूप में भी अच्छी खासी ठंड का अहसास हो रहा है। बताया जा रहा है कि आज रात न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि एक दो दिन मौसम परिवर्तनशील रहेगा। उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के प्रभावी रहने के कारण ठंड और बढ़ सकती है। लगातार तीसरे दिन भी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के प्रभावी रहने की संभावना के कारण कहीं-कहीं मध्यम से घनी धुंध और दिन व रात के तापमान में गिरावट की संभावना है।

मुख्यमंत्री की पहल से बिजली की रौशनी से जगमगाया इत्तेपारा

सालभर से लालटेन और दीया ही था सहारा

सुकमा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विकास तेज गति से हो रहा है। बस्तर अंचल के दूरस्थ इलाकों में भी प्राथमिकता से बुनियादी सुविधाएं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली पहुंचाई जा रही है। सुकमा जिले के इत्तेपारा गांव में एक वर्ष बाद लोगों को फिर से बिजली मिलने लगी है। पूरा गांव रौशनी से जगमगा उठा है।

सालभर से लालटेन और दीये के युग में जी रहे इत्तेपारा के ग्रामीणों के लिए गांव में फिर से बिजली का आना विकास की नई रौशनी के समान है। दुर्गम भौगोलिक बसाहट थी उस पर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित गांव की किस्मत अब बदलने जा रही है। अंधेरे में रहने की परेशानी छंटने से ग्रामीण अत्यन्त प्रसन्न है।

बिजली न होने से होने वाली दिक्कतों के संबंध में ग्रामीण बताते है कि उन्हें शाम ढलते तक अपने पूरा काम धाम निपटाकर घरों में बंद हो जाना पड़ता था और रात में मजबूरीवश कहीं आने-जाने के लिए लालटेन और दीया का ही उनका सहारा था। बहरहाल, लालटेन और दीए के युग में जी रहे इत्तेपारा के ग्रामीणों के लिए गांव में विद्युतीकरण का होना विकास का उजाला लेकर आया है। इसके लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का धन्यवाद किया।

गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को 3 फरवरी को माओवादी आतंक प्रभावित सुकमा जिले के प्रवास के दौरान ग्राम इत्तेपारा का भ्रमण किया था और लोगों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उनके गांव में पिछले एक वर्ष से बिजली नही है। एक वर्ष पहले यहां बिजली थी। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

शिक्षक-शिक्षिकाओं का संभाग स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम

जगदलपुर। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संभाग स्तर पर शिक्षक-शिक्षिकाओं का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन बस्तर अकादमी ऑफ आफ डान्स आर्ट एण्ड लिटरेचर आसना (बादल) में गुरूवार 08 फरवरी 2024 को किया गया। जिसमें बस्तर संभाग के प्रत्येक विकासखंड के शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा भाग लिया गया। मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में बाल अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, आगजनी के खतरे संबंधी जानकारी, शाला आपदा प्रबंधन, जंगली जानवरों से सुरक्षित दूरी कैसे रखें, बाल यौन शोषण, विशेष इलाज वाली परिस्थिति, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं उपाय, प्राथमिक चिकित्सा की उपयोगी बातें और प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल की अशुद्धता से होने वाले खतरे एवं इसके उपाय, हाथ धोने के सही तरीके इत्यादि विभिन्न जानकारी दी गई। राज्य प्रशिक्षक डॉ. श्रवण और राज्य समन्वयक के द्वारा विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

12 फरवरी से 23 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

मनेंद्रगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा 28 दिसम्बर 2023 को हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 की समय-सारणी जारी किया गया है जिसके अनुसार 01 मार्च 2024 से 23 मार्च 2024 तक परीक्षा का आयोजन निर्धारित की गई है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान न हो इस हेतु जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 5(1)(2), धारा-6 एवं धारा 10 (2) के तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 में उल्लेखित प्रावधानों के साथ पठित भारतीय दण्ड प्रक्रिय संहिता की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 12 फरवरी 2024 से 23 मार्च 2024 तक की अवधि में (अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित) अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क, ख, एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय के लिए प्रतिबंध लगाया है।

मैनपाट महोत्सव स्थल में दुकान निर्माण के लिए आवेदन 21 तक

अंबिकापुर। मैनपाट महोत्सव 2024 का आयोजन 23, 24 एवं 25 फरवरी को निर्धारित है। महोत्सव स्थल में फुड जोन हेतु दुकान का निर्माण किया जाना है। जनपद पंचायत मैनपाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि निर्माण किए जाने वाले 40 दुकानों हेतु इच्छुक व्यक्ति 21 फरवरी तक जनपद पंचायत मैनपाट कार्यालय में उपस्थित होकर दुकान आबंटित करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रति दुकान तीन दिन हेतु निर्धारित शुल्क 6100 रुपए देय होगा, दुकानों हेतु समूह को प्राथमिकता दी जाएगी, दुकान मैनपाट महोत्सव दिवस 3 दिन के लिए आबंटित होगी। व्यवसायी को एक मुक्त राशि जमा करना अनिवार्य होगा। दुकान 15×15 साईज के साथ एक कुर्सी, एक नग टेबल के साथ एक बल्ब शामिल है। अलग से सामान लेने पर अतिरिक्त शुल्क देय होगा, किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैनपाट का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य तथा बाध्यकारी होगा।

कलेक्टर, एसपी की विद्यालयों के संस्था प्रमुखों के साथ बैठक

अंबिकापुर। कलेक्टर श्री विलास भोस्कर तथा पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिले के सभी अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों के संस्था प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्कूल प्रबंधन, कानूनी प्रावधानों, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के अनुकूल व्यवहार, शिक्षकों की भूमिका आदि के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विलास भोस्कर ने विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को कहा कि विद्यालय की शुरुआत प्रसन्नता के साथ हो, बच्चों में विद्यालय के प्रति भय न रहे। बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, अत: भविष्य संवारने में अपनी भूमिका निभाएं। शिक्षक बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, उनके अंदर स्वप्रेरणा जागृत करें, यह तभी सम्भव है जब पढ़ाई के साथ उनकी मानसिक क्षमता उभारने का प्रयत्न किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में एक कक्षा मनोविज्ञान की हो, जिससे बच्चों की सोच विकसित हो। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा।

सरोदा डैम के पास जंगल में जुआ खेलते 9 पकड़ाए

कबीरधाम। जिले में अपराध रोकने, अवैध जुआ-सट्टा, शराब, गांजा की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार कारवाई कर रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कवर्धा के सरोदा डैम के पीछे जंगल से 9 जुआरियों घेराबंदी कर पकड़ा है। ये सभी जुआरी रात के अंधेरे में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 1 लाख 48 हजार 120 रुपए जब्त भी किया है। पुलिस सभी आरोपिओं के खिलाफ केस दईज कर जुआ खेलाने वाले मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार, गुरुवार देर शाम मुखबिर से सूचना मिली कि कवर्धा में सरोदा डैम के पीछे जंगल में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर सभी आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से 9 जुआरियों को पकड़ा और उनसे 01 लाख 48 हजार 120 रुपए जब्त किया। जिसके बाद सभी आरोपियों को थाना लाकर उनके खिलाफ संबंधित धाराओ में केस दर्ज किया गया है।

महतारी वंदन योजना: प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में हो रहा शिविर का आयोजन

■ योजना के कारगर क्रियान्वयन हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त

जगदलपुर। राज्य शासन के द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदन योजना 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. द्वारा बस्तर जिले में उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश कुमार सर्वे को नोडल अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अरुण कुमार पाण्डेय को सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु कर्तव्यस्थ

किया गया है। वहीं विकासखण्ड स्तर पर सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी एवं संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतुनियुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव ग्राम प्रभारी एवं संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक ग्राम प्रभारी होंगी।

महतारी वंदन योजनान्तर्गत पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए जिले में 05 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक ग्राम पंचायत अंतर्गत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही नगरीय निकायों में चयनित जगहों पर शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। उक्त शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही किये जाने हेतु नामजद अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

ज्ञातव्य है कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत ऑनलाईन व ऑफलाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है। अनन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व-सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

महतारी वंदन योजनांतर्गत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी होने की स्थिति में योजनांतर्गत अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद व विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो वे भी योजनांतर्गत अपात्र होंगी। महतारी वंदन योजनांतर्गत आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निरूशुल्क होगी।

मोदी की हर गारंटी पूरा करेंगे, राजिम कुंभ को मिलेगी पहचानः मुख्यमंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की ओर से बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर दिए गए अभिभाषण पर शुक्रवार को चर्चा के बाद राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि हमने प्रदेश में सुशासन की स्थापना का संकल्प लिया है। हम छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन में खुशहाली और समृद्ध लाने के लिए पीएम मोदी हर गारंटी को पूरा करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता जीर्ण-शीर्ण हो चुके प्रदेश के वित्तीय-ढांचे को फिर से मजबूत करने और फिर से कुशल वित्तीय प्रबंधन की स्थापना करने की होगी। नवा रायपुर मध्य भारत का इनोवेशन हब बनेगा। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। राजिम को देश के मानचित्र पर महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में पहचान दिलाई जाएगी। राजिम कुंभ के आयोजन की परंपरा को फिर शुरू होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने हमें विरासत में खाली खजाना और भारी कर्ज सौंपा है। अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संसाधनों का इंतजाम हमारे सामने बड़ी चुनौती हो सकती थी, लेकिन जनता-जनार्दन के आशीर्वाद, विश्वास, समर्थन और सहयोग से ऐसी तमाम तरह की चुनौतियों पर विजय पाने में हम कामयाब हो रहे हैं। पीएम का फोकस किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं पर रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए जो गारंटियां दी हैं, उनका फोकस भी मुख्य रूप से इन्हीं वर्गों पर है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, सामाजिक और भौतिक विकास में तेजी लाने के लिए अधोसंरचनाओं का निर्माण करना, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, संस्कार, रोजगार, व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ राज्य सरकार काम करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित-भारत के निर्माण और भारत को दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इन लक्ष्यों को हासिल करने में छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे अनुपूरक बजट का उद्देश्य मोदी जी की गारंटियों के क्रियान्वयन की शुरुआत करना था, तीसरा अनुपूरक बजट शुरू हो चुके काम को आगे बढ़ाने तथा गति देने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसी सत्र में वर्ष 2024-25 के लिए हमारी सरकार पहला मुख्य बजट प्रस्तुत

करने जा रही है, जो अनेक मायनों में ऐतिहासिक बजट होगा।

18 लाख परिवारों को आवासों की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने के क्रम में शपथ-ग्रहण के दूसरे ही दिन कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख परिवारों के आवासों के निर्माण के लिए हमारी सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर आवासों के निर्माण के लिए 3799 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान पारित कराया गया था। इसी तरह मोदी जी की गारंटी के अनुरूप पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 को राज्य के 12 लाख किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इस तीसरे अनुपूरक अनुमान में कृषक उन्नति योजना के लिए 12000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ में अब तक रिकॉर्ड धान खरीदी

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमने राज्य में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की और इस साल प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाया है। हमने इस साल 144.92 लाख मीटरिक टन धान खरीदी की है। इस साल 24 लाख 72 हजार 440 किसानों ने धान बेचा है, जो पिछले साल के 23 लाख 42 हजार से 1 लाख 30 हजार ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 37 लाख मीटरिक टन ज्यादा धान उपार्जित किया गया है। हमने न सिर्फ अब तक की सर्वाधिक मात्रा में धान की खरीदी की है, बल्कि इस बार धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी सर्वाधिक रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मांग पर हमने धान खरीदी की अवधि में बढ़ोतरी भी की थी। अवधि बढ़ाने से 19 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए और वे भी अपना धान बेच पाए। चालू खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश में 130 लाख मीटरिक टन धान के उपार्जन का अनुमान था, लेकिन रिकॉर्ड खरीदी के चलते अनुमानित उपार्जन का आंकड़ा काफी पीछे छूट गया है। राज्य में कस्टम मिलिंग का काम भी तेजी से जारी है। उपार्जित धान 144.92 लाख टन में से 106.04 लाख टन धान के उठाव का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 100.94 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है।

महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती देने, लैंगिक और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना शुरू कर दी गई है। यह योजना भी मोदी जी की गारंटियों में शामिल है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक पात्र विवाहित महिला को 12,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरे अनुपूरक बजट में इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना को कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 5 फरवरी 2024 से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। कल 7 फरवरी तक इस तरह केवल 3 दिनों में ही 16 लाख 82 हजार आवेदन भरे जा चुके हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में बहुत उत्साह है। उनका उत्साह और खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी और संतुष्टि मिली रही है।

रामलला दर्शन योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत का सदियों का सपना पूरा हो गया है। रामलला प्रत्येक भारतीय की आत्मा में रचे-बसे हैं। छत्तीसगढ़ से भगवान श्रीराम का अटूट नाता है। वे हमारे भांजे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। राज्य सरकार हर साल रामलला दर्शन योजना के तहत हजारों यात्रियों को रामलला के दर्शन कराएगी।

चारधाम परियोजना की तर्ज पर 5 शक्तिपीठों का होगा विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रदेश को प्रभु श्रीराम के साथ-साथ शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहां अनेक शक्तिपीठ हैं। ये शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ हमारी संस्कृति के भी केंद्र हैं। राज्य शासन ने चारधाम परियोजना की तर्ज पर 05 शक्तिपीठों- कुदरगढ़, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को विकसित करने के लिए कार्ययोजना के निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया है।

तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना शुरू होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए आदिवासी बन्धुओं के लिए हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर को अब 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है। कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है।

यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी की परीक्षाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अपने भ्रष्टाचारी हाथों से प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य का गला घोंटा है। उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। पीएससी की परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों से बड़ी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। मोदी जी ने इन शिकायतों की जांच कराने की गारंटी दी थी। उनकी गारंटी के अनुरूप पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। इस मामले में ईओडब्लू ने पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव पर धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले पर कल एफआईआर दर्ज कर ली है। पीएससी की परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता हो इसके लिए हम इसे यूपीएससी की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया है।

अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से होगी योजनाओं की निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए खनिज के परिवहन और परमिट को मैनुअल पद्धति से जारी करने का आदेश पारित करा दिया था। हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए प्रदेश में खनिज के परिवहन और परिमिट को पुनः ऑनलाईन कर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण के वादे को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए 25 दिसंबर 2023 को अटल जी की जयंती के अवसर पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लांच कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे अनुपूरक में केंद्र शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित स्वास्थ्य, चिकित्सा, महिला सुरक्षा एवं महिला कल्याण, अधोसंरचना, युवा कल्याण, विद्युत जैसे विषयों के लिए भी तीसरे अनुपूरक में अनुमान प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें सदन ने पारित कर दिया है।

कानून का राज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित है। हम छत्तीसगढ़ से माओवादी-आतंकवाद के पूरी तरह से उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हैं। माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार शांति और सुरक्षा स्थापित करते हुए तेजी से बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी। हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राज्य में फिर से भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया है।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग, स्टेशन में मचा हड़कंप

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक आग लगने से बिलासपुर स्टेशन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुंचे आरपीएफ के जवानों ने आग पर काबू पाया। घटना बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफार्म 2 में आज सुबह 6 बजे घटित हुई। कोरबा रवाना होने के लिए प्लेटफार्म में खड़ी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच एम1 से अचानक आग की लपटें उठाने लगी। आग की वजह से कोच के सीट, बेडरोल पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि स्टेशन में अचानक लाइट बन्द हुई, जिसके बाद कोच से धुंआ उठने लगा। प्रथम दृष्टया आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, फिलहाल, पूरी घटना की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आगजनी की मुख्य वजह क्या रही।

सांसद सोनी ने पीएम और रेल मंत्री से की रेल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग

रायपुर। लोकसभा सत्र के शून्य काल में गुरुवार को रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने रेलवे से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने ट्रेन की लेट लतीफी और रद्द होने वाली गाड़ियों के संबंध में जनता को हो रही परेशानियों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से ट्रेनों को समय पर संचालित करने की मांग की। सुनील सोनी ने कहा कि आजादी के बाद से छत्तीसगढ़ में रेल मंत्रालय को सर्वाधिक राशि करीब 7000 करोड़ प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई है जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में वंदे भारत जैसी ट्रेनों का संचालन एवं निर्माण किया जा रहा है, जो की अत्यंत प्रशंसनीय है। सांसद ने पहले जिन स्टेशनों में स्टॉपेज होता था वहां फिर से स्टॉपेज की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में और फास्ट ट्रेनें चालू हों।

विधानसभा के वर्ष 2024 के वार्षिक कैलेंडर और डायरी का हुआ विमोचन

रायपुर। विधानसभा सभा अध्यक्ष डॉ. रमन

सिंह ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में आज छत्तीसगढ़ विधान सभा के वर्ष 2024 के वार्षिक कैलेंडर व डायरी का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, विधायक श्री किरण सिंहदेव और विधानसभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा मौजूद रहे।

4 जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित, बृजमोहन ने सदन में की घोषणा

रायपुर। कोरोना काल में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बिना निविदा सामग्री खरीदने का मामला सदन में उठा। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों नियमों का पालन नहीं किए जाने की बात कहते हुए चार जिलों के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारियों को सदन में ही निलंबित करने की घोषणा की।

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बिना निविदा सामग्री खरीदने का मामला उठाते हुए सवाल किया कि क्या छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम में एनसीसीएफ, नेकाफ, केंद्रीय भंडार और स्व सहायता समूह से बिना निविदा खरीदी करने की छूट दी गई है? मुझे जानकारी है कि करीब 50 करोड़ रुपए की सामग्री की ख़रीदी की गई है। क्या इसकी जांच की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि करीब 36 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है। जो छूट लेनी चाहिए थी, वह छूट नहीं ली गई। नियमों का पालन नहीं किया गया। सूरजपुर, मुंगेली, बीजापुर, कोंडागाँव जैसे जिलों में खरीदी की गई। सूरजपुर ज़िले में 11 करोड़ 36 लाख, मुंगेली में 99 लाख 95 हज़ार, बस्तर में 20 करोड़ 47 लाख, बीजापुर में 55 लाख 4 हजार और कोंडागाँव में 3 करोड़ रुपए की ख़रीदी की गई थी।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक जिले के जिला शिक्षा

अधिकारी को निलंबित किया गया है।

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि कोरोना की आड़ में बड़ा खेल खेला गया। सदन की कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए। मंत्री गड़बड़ी को स्वीकार कर रहे हैं। फिर इस पर कार्रवाई कब तक होगी। बृजमोहन अग्रवाल ने की चार जिलों के ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा। विनोद राय, एल्मा, प्रमोद ठाकुर और राजेश मिश्रा को निलंबित किया।

डीएमएफ मद से स्वामी आत्मानंद स्कूल में हुए खर्च की जांच कर सरकार लाएगी श्वेत पत्र

डीएमएफ मद से स्वामी आत्मानंद स्कूल में खर्च की गई रकम का मुद्दा लगातार दूसरे दिन भी सदन में उठा। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए डीएमएफ मद से स्वामी आत्मानंद स्कूलों में हुए खर्च की जांच कर सरकार द्वारा श्वेत पत्र लाए जाने की घोषणा की। भाजपा विधायक आशाराम नेताम ने डीएमएफ मद से स्वामी आत्मानंद स्कूल में खर्च की गई राशि का उठाया मामला। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि स्कूलों के जीर्णोद्धार पर इतनी राशि खर्च कर दी गई जितने में एक नया स्कूल बन जाता। डीएमएफ की राशि निर्माण कार्यों में खर्च कर दी गई।

नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि आपने कहा कि कलेक्टरों ने ये राशि खर्च की है तो कलेक्टरों पर कार्रवाई करें। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने पूछा कि इस मामले में क्या सरकार श्वेत पत्र जारी कर सकती है? इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में जिस तरह से निर्माण कराया गया है। इसकी विस्तृत जांच कराकर अगले सत्र तक सरकार श्वेत पत्र जारी कर देगी।

छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को बढ़ावा देने पीपीपी मॉडल लाएगी सरकार : अग्रवाल

रायपुर। प्रदेश में होटल, मोटल और रिसॉर्ट का निर्माण और संचालन का मामला सदन में उठा। पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तुलना हिमाचल, उत्तराखंड, केरल जैसे राज्यों से नहीं कर सकते। राज्य में आने वाले समय में हम ऐसी पॉलिसी बनायेंगे कि पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट लोगों को लाकर पर्यटन को बढ़ावा देंगे।

नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूछा कि 42 होटल, मोटल और रिसॉर्ट बनाए गए थे। सरकार ने ज़मीन दी थी। 150 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इन होटल, मोटल और रिसॉर्ट का क्या हुआ? पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 18 का संचालन पर्यटन विकास निगम कर रहा है। 14 लीज पर है, और बाक़ी को लीज पर देने की तैयारी चल रही है।

महंत ने पूछा कि 22 मोटल, होटल और रिसॉर्ट की जानकारी दी गई है। आधे का बता दिया, आधा कहाँ गया? ज़मीन पर है या ऊपर चली गई? लीज पर दिए गए होटल, मोटल और रिसॉर्ट से कितनी राशि मिली? पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लीज पर दिए गए होटल, मोटल और रिसॉर्ट से 2 करोड़ 42 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली।

भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि संचालन नहीं होने की वजह से होटल, मोटल और रिसॉर्ट कबाड़ की तरफ़ बढ़ रहा है। कलेक्टरों को निर्देश दे दीजिए कि उसे दुरुस्त कर दें। टूरिस्ट जो आते हैं उन्हें कई सुविधा नहीं मिलती। बियर बार का प्रावधान करायें। कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम आसपास के गांव की स्व-सहायता समूह की महिलाओं को दे दें कि दाल भात सेंटर शुरू कर दें।

पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तुलना हिमाचल, उत्तराखंड, केरल जैसे राज्यों से नहीं कर सकते। राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमें सब्सिडी देनी होनी। राज्य में पर्यटन के लिए आठ-दस हजार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, तब जाकर पर्यटन का विकास हो सकेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक बस सर्किट बनाइए। लोगों को दर्शन कराए। इन होटल, मोटल और रिसॉर्ट का उपयोग भी होगा।

अमरजीत के घर फिर आ सकती है आईटी की टीम

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और उनके करीबियों पर आयकर के छापे के बाद आईटी का शिकंजा और अधिक कसता जा रहा है। आईटी अधिकारी ने सरगुजा कलेक्टर को पत्र लिखकर अमरजीत भगत के 13 करीबियों की प्रॉपर्टी की जानकारी मांगी है। यानी आईटी इन सबकी बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है।

आईटी की टीम ने 31 जनवरी को पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अंबिकापुर, रायपुर और सीतापुर स्थित निवास-बंगलों पर छापा मारा था। आईटी ने उनके ओएसडी, पीए सहित करीबी कारोबारियों पर एक साथ छापामार करवाई की थी। पांच दिनों तक आईटी की जांच चली। इस कार्रवाई में अमरजीत भगत के अंबिकापुर और रायपुर स्थित निवास से 2.5 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश और आभूषण जब्त किए हैं। सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर) के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस दौरान भगत के करीबी लोगों से भी टीम ने पूछताछ की और उनके पास से कई जमीनों के दस्तावेज बरामद किए। फिलहाल आईटी की टीम अंबिकापुर से वापस चली गई थी। लेकिन टीम ने अंबिकापुर कलेक्टर को पत्र लिखकर भगत के 13 करीबी लोगों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। इनके संबंध में विभाग ने पिछले पांच साल में जमीन की खरीदी और बिक्री की जानकारी मांगी है। साथ ही रियल इस्टेट कारोबार में निवेश या अन्य प्रॉपर्टी के साथ-साथ जमीन आवंटन के अलावा एफआरए और अन्य बेनीफिट की डीटेल उपलब्ध कराने का भी निवेदन किया है। गौरतलब है की जिन 13 लोगों का ब्यौरा मांगा गया है, इन लोगों के यहां पिछले दिनों आयकर टीम ने जांच-पड़ताल भी की थी।

रायपुर अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए मतदान

16 पदों के लिए मैदान में 57 प्रत्याशी

रायपुर। पिछली बार की तरह इस बार भी रायपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ता संघ का चुनाव शुक्रवार को कराया गया। मतदान सुबह 10:00 से शाम 5:00 तक हुआ। इस बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव संघ सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे 16 पदों के लिए 57 प्रत्याशी मैदान में है। कुल मतदाताओं की संख्या 2368 है।

ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नई कार्यकारिणी जो बनकर आएगी, वह वकीलों के हित में सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी। अधिवक्ताओं से संबंधित समस्या जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट कॉलोनी बनाने, कोर्ट परिसर में साफ सफाई, महिला टॉयलेट या पार्किंग की समस्या के मुद्दों को दूर करने को लेकर संघ द्वारा आवाज बुलंद किया जाएगा।

इस बार के मतदान को लेकर मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिला। विभिन्न पदों के लिए चुनाव में उतरे तमाम प्रत्याशी पूरे जोर शोर से मैदान में उतरकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही अधिवक्ताओं से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने की बात कह रहे हैं। तमाम प्रत्याशी पूरे जोर शोर से मैदान में उतरकर अपनी जीत का दावा करने लगे हैं।

रायपुर जिला अधिवक्ता संघ का इलेक्शन सन 1989 से होता आ रहा है। हर 2 साल के बाद फिर से चुनाव की प्रक्रिया कोर्ट परिसर में की जाती है। इस बार भी अधिवक्ताओं से संबंधित समस्या या फिर कोर्ट परिसर से संबंधित समस्याओं को लेकर सुलझाने का दावा प्रत्याशी कर रहे हैं। विभिन्न पदों के लिए चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी अपने-अपने तरीके से अपने वोटरों को साधने की कोशिश कर थे।

उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश के बाद पानी टंकी के निर्माण में आई तेजी

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम देवरहट में पानी टंकी (उच्च स्तरीय जलागार) के निर्माण का काम तेजी से शुरू हो गया है। विगत दिनों एक कार्यक्रम में शामिल होने देवरहट पहुंचे उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री साव से ग्रामीणों ने पानी टंकी के निर्माण में लेट-लतीफी की शिकायत की थी। श्री साव ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यस्थल का निरीक्षण कर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ पानी टंकी का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद विभाग ने तुरंत ही पानी टंकी का निर्माण पूर्ण करने तेजी से काम प्रारंभ कर दिया है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यस्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से कहा था कि जल जीवन मिशन शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण कार्य त्वरित गति से शुरू कर दिया गया है। इसका काम शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि देवरहट में हर घर तक शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए करीब एक करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय जलागार बनाया जा रहा है। इसके निर्माण से गांव के 437 परिवारों को स्वच्छ पेयजल का लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर तेजी से इसका निर्माण पूर्ण किया जा रहा है।

आरक्षण पर नेहरू और मोदी की सोच में फर्क क्या?

संजय तिवारी

जिस दिन नरेन्द्र मोदी संसद के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, वो अपनी सरकार में महिला, नौजवान आदि के नाम पर किये गये काम गिना रहे थे। इस बीच किसी विपक्षी सांसद ने यह कहकर टोक दिया कि आपने अल्पसंख्यकों का नाम नहीं लिया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी इतने नाराज हुए कि लगभग बिफरते हुए कहा कि कब तक समाज को टुकड़ों में बांटते रहोगे। अगर महिला कहा तो क्या सारी महिलाएं उसमें शामिल नहीं हैं? अगर नौजवान कहा तो क्या सारे नौजवान उसमें शामिल नहीं है? उनकी बात सही थी। सरकार के लिए नागरिकों में कोई भेद नहीं होता। इसलिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का बंटवारा क्योंकर होना चाहिए? धार्मिक अल्पसंख्यकों का नाम लिये जाने पर मोदी को गुस्सा संभवत: इसलिए आया क्योंकि वो हिन्दू वोटबैंक द्वारा चुनकर आते हैं। वहां वो समता और समानता का सिद्धांत कायम रख सकते हैं लेकिन वहीं पर जब बात दलितों की आती है तो उनकी भाषा बदल जाती है। उसी संसद में जब वो राज्यसभा में बोलने पहुंचे तो उनका यह समतावादी सिद्धांत स्वयं वोटबैंक की राजनीति का शिकार हो गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक पत्र की कुछ पंक्तियां पढ़ी जिसे उन्होंने उस समय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा था। अंग्रेजी में लिखे इस पत्र के पहले पैरा का अनुवाद करते हुए मोदी ने बताया कि पंडित नेहरु ने लिखा था मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे। जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि नेहरु की चिट्ठी का सिर्फ उतना ही हिस्सा पढ़ा जितना उनको राजनीतिक रूप से फायदेमंद लगा। वरना जिस पैरे का आधा हिस्सा ही मोदी ने पढ़ा था, उसी चिट्ठी के उसी पैरे में नेहरु लिखते हैं मैं चाहता हूं कि देश हर मामले में फर्स्ट क्लास बने। जैसे ही हम सेकेण्ड रेट को बढ़ावा देंगे, हम खत्म हो जाएंगे। इसके बाद नेहरु ने यह भी लिखा है कि पिछड़े समूहों के उत्थान का सिर्फ एक रास्ता हो सकता है कि उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा की ओर ले आया जाए खासकर तकनीकी शिक्षा की ओर। लेकिन अगर हम जाति या धर्म के नाम पर आरक्षण की दिशा में आगे बढते हैं तो हम तेज तर्रार और प्रतिभावान लोगों को खो देंगे और दूसरे या तीसरे दर्जे का (देश) होकर रह जाएंगे। अपनी चिट्ठी में नेहरु आगे लिखते हैं मुझे यह जानकर दुख हुआ कि सांप्रदायिक विचारों के आधार पर आरक्षण का यह व्यवसाय कितना आगे बढ़ गया है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पदोन्नति भी कभी-कभी सांप्रदायिक और जातिगत विचारों पर आधारित होती है। इस तरह से न केवल मूर्खता होती है, बल्कि विनाश भी होता है। आइए हम पिछड़े समूहों की हर तरह से मदद करें लेकिन दक्षता की कीमत पर कभी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो चिट्ठी का उतना ही हिस्सा पढ़ा जितना उनके लिए राजनीतिक रूप से सही था क्योंकि इस हिस्से को पढ़कर वे कांग्रेस पार्टी को आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी साबित करना चाहते थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा भी कि ये लोग (कांग्रेस) तो जन्म से आरक्षण के विरोधी हैं। लेकिन इस पूरी चिट्ठी को पढ़ने के बाद तो शायद वे लोग भी नेहरु का विरोध नहीं करेंगे जिन लोगों तक मोदी यह संदेश पहुंचाना चाहते थे। नेहरु ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे उन्हें दलित विरोधी साबित किया जाए। हालांकि एक सत्य यह भी है कि संविधान सभा के निर्णय के चलते उनकी ही सरकार में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सरकारी नौकरी में दस वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया। लेकिन दस वर्ष पूरे होने के बाद भी समय समय पर कांग्रेस की सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों का दायरा बढ़ाया गया और अधिक से अधिक जातियों तक सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रतिशत भी बढ़ाया गया। जहां तक मोदी द्वारा संसद में नेहरु के भाषण का उल्लेख है तो उन्होंने यह बोलकर एक तरह से सेल्फ गोल ही किया है।

समान नागरिक संहिता का भारत में प्रवेश

जयसिंह रावत

उत्तराखण्ड विधानसभा से समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) का विधेयक पास कराना सम्पूर्ण भारत में इस संहिता को लागू कराने का ट्रायल माना जा सकता है। क्योंकि बिना राष्ट्रपति या केन्द्र सरकार की अनुमति से न तो यह संहिता लागू हो सकती है और ना ही उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना केन्द्रीय नेतृत्व की सहमति के इतने बड़े और विवादित मुद्दे को छेड़ सकते थे। माना जाता है कि पंडित नेहररू ने भी 1951-52 का आम चुनाव समान नागरिक संहिता पर ही लड़ा था जिसका उन्हें लाभ मिला और उन्होंने 19555 और 56 में हिन्दुओं से संबंधित नागरिक संहिताएं (यूसीसी) पारित करवा दीं। परिस्थितियों को देख कर साफ लगता है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व समान नागरिक संहिता का ट्रायल उत्तराखण्ड में कराया जा रहा है। यूसीसी पर सुशील मोदी की अध्यक्षता में गठित 17 सदस्यीय कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति की 3 जुलाइ 2023 की बैठक के बाद सुशील मोदी ने प्रेस को बताया था कि इस संहिता से जनजातियों को अलग किया जा सकता है और यही प्रावधान उत्तराखण्ड की समान नागरिक संहिता में भी किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकाल करना बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन धामी सरकार द्वारा नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी का गृह मंत्री और विधि आयोग से मिलना सामान्य बात नहीं है। ये मुलाकातें दर्शाती हैं कि धामी सरकार का यह कदम अमित शाह के आर्शिवाद और मार्ग दर्शन के नहीं है। नागरिक संहिता की ड्राफ्ट कमेटी ने 2 जून 2023 को दिल्ली में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी से भेंट की थी। इसके बाद जस्टिस रंजना देसाई ने मुख्यमंत्री धामी के साथ 3 जुलाइ 2023 को इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह से देर सांय मुलाकात की। उसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद प्रेस से बातचीत करते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता की तैयारियों से भली भांति अवगत हैं। इन मुलाकातों से साफ जाहिर है कि उत्तराखण्ड का यूसीसी कानून अकेले पुष्कर सिंह धामी के दिमाग की उपज नहीं बल्कि एक सुनियोजित चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है।

जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी की 2 जून को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात के बाद 14 जून को आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता पर जन साधारण और धार्मिक संगठनों से राय शुमारी करना भी केन्द्र सरकार की इस संहिता को लागू करने के प्रति बढ़ती रुचि के साथ ही सरकार के उत्तराखण्ड की नागरिक संहिता से सीधे लिंक को ही दर्शाता है। क्यों 21वां विधि आयोग 2018 की अपनी रिपोर्ट में साफ कह चुका था कि भारत में न तो समान नागरिक संहिता जरूरी है और ना ही वांछित है। उस आयोग का गठन भी मोदी सरकार ने ही किया था और उसके पास भी यह विषय विचारणीय था। यही नहीं उत्तराखण्ड के मुख्समंत्री ने पहले कहा था कि देसाई कमेटी जून तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। उन्होंने यह भी कहा था कि संहिता का ड्राफ्ट बन कर प्रेस में है। लेकिन कमेटी की विधि आयोग और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकातों के बाद उसकी रिपोर्ट को इतने विलम्ब से 2 फरबरी को आने का मतलब विधि आयोग और गृह मंत्रालय के सामंजस्य से रिपोर्ट को ऐसा बनाना भी हो सकता है जो कि स्वयं केन्द्र सरकार के काम आए।

जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 21 फरबरी 2020 को 22वें विधि आयोग का गठन 3 साल के लिए हुआ था जिसका कार्यकाल फरबरी 2023 में पूरा होने के बाद उसे 31 अगस्त 2024 तक का विस्तार दिया गया है। भारत का विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की एक अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ इसे गठित किया जाता है और आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार को (रिपोर्ट के रूप में) सिफारिशें करता है। वर्तमान आयोग के समक्ष भी विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा समान नागरिक संहिता के मामले को संदर्भित किया गया है। आयोग को अपने मूल कार्यकाल की समाप्ति के बाद अब यूसीसी पर तत्परता दिखाने को सीधा मतलब भारत सरकार का इस मुद्दे को अपनी प्रथमिकता में लाना है। तत्परता भी तब दिखाई जा रही है जबकि उसका मूल कार्यकाल ही समाप्त हो गया। सरकार का इस विषय पर इतनी रुचि दिखाने का मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव ही हो सकता है।

संविधान के नीति निर्देशक तत्व संख्या 44 में सरकार से भारत के पूरे क्षेत्र के अंन्दर समान नागरिक संहिता लागू करने की अपेक्षा की गई है। मौलिक अधिकारों संबंधी अनुच्छेद 24 से 28 की रुकावटों, देश की सांस्कृतिक विधिता और अनुसूची 5 और 6 की विशेष परिस्थितियों के कारण भारत की सरकारें अब तक इसे लागू नहीं कर सकीं। मोदी सरकार धारा 370 को तक हटाने का बहुत ही मुश्किल काम आसानी से कर गई। लेकिन वह भी देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता तथा संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए "यूसीसी" को लेकर ठिठक गई। यह संहिता सीधे तौर पर लोगों की आस्था और धार्मिक परम्पराओं के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र से भी संबंधित है और सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच 1973 में कह चुकी है कि संसद के पास संविधान संशोधन के व्यापक अधिकार तो हैं लेकिन असीमित अधिकार नहीं हैं। उसी समय कोर्ट का यह भी कहना था कि संविधान की मूल भवना से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो सुप्रीमकोर्ट को ऐसे संशोधनों की समीक्षा का अधिकार है। इसलिए उत्तराखण्ड की यूसीसी को भी कोर्ट में चुनौती अवश्य मिलेगी।

जहां तक उत्तराखण्ड में "यूसीसी" का सवाल है तो राज्य विधानसभा को कानून बनाने का पूरा अधिकार है मगर संविधान के दायरे से बाहर जाने का अधिकार नहीं। यह संविधान की समवर्ती सूची का है और अनुच्छेद 254(1) कहता है कि समवर्ती सूची के विषयों पर संसद के साथ ही विधानसभा भी कानून बना तो सकती है लेकिन अगर दोनों के कानून टकराते हैं तो केन्द्र के कानून के आगे राज्य का कानून स्वत: अमान्य हो जाएगा।

चूंकि इस विषय पर पहले ही संसद द्वारा पारित हिन्दू मैरेज ऐक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून मौजूद हैं, जिन्हें बदलने का अधिकार राज्य विधानसभा को नहीं है। लेकिन इसी अनुच्छेद के 254 (2) में कहा गया है कि अगर समवर्ती सूची में राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून को राष्ट्रपति अनुमति देते हैं तो वह कानून उस राज्य की सीमा के अंदर लागू हो सकता है। जाहिर है कि इसी धारा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड में "यूसीसी" बनाने की पहल हो रही है और बिना केन्द्र सरकार के आश्वासन या प्रोत्साहन के राज्य सरकार द्वारा यह पहल नहीं हो सकती थी। इस यूसीसी में मौलिक अधिकारों के हनन के साथ ही लिव इन रिलेशन, सम्पति का उत्तराधिकार, सरकारी कर्मचारियों तथा दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासियों पर बंदिशें जैसी कुछ एंसी खामियां हैं जो अदालती हस्तक्षेत्र के लिए पर्याप्त कारण है। ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार ट्रायल के तौर पर उत्तराखण्ड में यह संहिता परखना चाहती है और देखना चाहती है कि इसके सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक प्रभाव क्या हो सकते हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-3)

गतांक से आगे...

मैं उपनिषद् में प्रतिपादित अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप को कभी भी अस्वीकार न करूँ तथा वह ब्रह्म भी हमारा कभी परित्याग न करे। (वह) मुझे सदैव अपने सामीप्य का बोध कराता रहे। (उस ब्रह्म के साथ मेरा तथा मेरे साथ उस ब्रह्म का) प्रगाढ़ सम्बन्ध सतत बना रहे। उपनिषदों में वर्णित जो समस्त धर्म हैं, वे सभी उस परमात्म तत्त्व में निरत मुझमें सदैव प्रकाशित होते हुए स्थिर रहें। हे परमात्मन् ! त्रिविध ताप शान्त हों।

अब (ईश प्रार्थना के बाद) महोपनिषद् के व्याख्यान का शुभारम्भ किया जा रहा है। सृष्टि के आदि में एकमात्र भगवान् नारायण ही थे। इनके अतिरिक्त ब्रह्मा, रुद्र, आप: (जल), अग्नि एवं सोम आदि देवगण नहीं थे। ये द्युलोक तथा पृथ्वीलोक भी नहीं थे और न ही नक्षत्र, चन्द्रमा एवं सूर्य आदि ही थे। ऐसी स्थिति में उन (विराट् पुरुष) को एकाकी रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।

उन (विराट् पुरुष) का अन्त:करण में स्थित ध्यान यज्ञस्तोम अर्थात् श्रेष्ठ यज्ञ कहलाया। उनके द्वारा एक कन्या एवं चौदह पुरुष प्रादुर्भूत हुए। जिनमें से चौदह पुरुष ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय सहित दस इन्द्रियाँ, एकादश-तेजस्वी मन, द्वादश अहंकार, तेरह और चौदह क्रमश: प्राण और आत्मा हैं तथा पन्द्रहवीं बुद्धि कन्या के नाम से कही गयी है। इनके अलावा पाँच सूक्ष्मभूत रूपी तन्मात्राएँ एवं पाँच महाभूत आदि इन पच्चीस तत्त्वों के संयोग से एक विराट् पुरुष के शरीर का निर्माण हुआ।

उस (विराट् शरीर) में ही परमात्मरूप आदिपुरुष ने प्रवेश किया। (इन पच्चीस तत्त्वों से संयुक्त पुरुष से) प्रधान संवत्सर आदि प्रकट नहीं होते। (अपितु) आदि पुरुष के कालरूप संवत्सर से ही (संवत्सर) प्रादुर्भूत हुए हैं।

क्रमश: ...

भूमकाल दिवस

संजय पोखरियाल

भारत अपनी स्वतंत्रता का 'अमृत महोत्सव' मना रहा है। ऐसे में देश के उन अमर सपूतों को याद किया जाना चाहिए जो प्राण हथेली पर लेकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। इतिहास में स्वतंत्रता के अनेक नायकों का वर्णन मिलता है, परंतु बहुत से ऐसे नायक भी हैं, जिनके साथ इतिहास न्याय नहीं कर सका है। मुख्य रूप से 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर कांग्रेस के नेताओं का इतना अधिक प्रभाव है कि उसके आवरण में देश के विविध हिस्सों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले बहुत से नायक गुमनामी में धकेल दिए गए। वर्ष 1910 में बस्तर में आदिवासी समाज के आंदोलन 'भूमकाल' का नेतृत्व करने वाले गुंडाधुर इतिहास के ऐसे ही गुमनाम नायक हैं।

भूमकाल आंदोलन की बुनियाद वर्ष 1891 में पड़ी जब अंग्रेजों ने बस्तर के तत्कालीन राजा रूद्र प्रताप देव के चाचा कालेंद्र सिंह को दीवान पद से हटा दिया। रूद्र प्रताप देव अंग्रेजों के प्रति समर्पित राजा थे, लेकिन दीवान के रूप में प्रशासन का जिम्मा उनके चाचा कालेंद्र सिंह के पास था और वे इसे बेहतर ढंग से निभाते भी थे। आदिवासी समाज में उनकी अच्छी लोकप्रियता थी। ऐसे में कालेंद्र सिंह को दीवान पद से हटाकर पंडा बैजनाथ को बस्तर का प्रशासन सौंपा जाना आदिवासियों को पसंद नहीं आया। जंगल बचाने के नाम पर आदिवासियों को उनके ही जंगलों से दूर किया जाने लगा। साथ ही उनके मतांतरण का प्रयास भी किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में, कालेंद्र सिंह ने सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए आदिवासियों को संगठित किया और गुंडाधुर के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र भूमकाल आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई। उस दौर में गुंडाधुर की अधिकतम लोगों तक ऐसी पहुंच थी कि उनके विषय में अनेक किंवदंतियां फैलने लगीं। कोई कहता कि गुंडाधुर को उड़ने की शक्ति प्राप्त है तो कोई कहता कि वह लड़ाई के समय अपने जादू से अंग्रेजों की गोलियों को पानी बना देगा। इन किंवदंतियों से इतर गुंडाधुर की जमीनी योजना-रचना ऐसी थी कि आंदोलन शुरू होने से पूर्व अंग्रेजों को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। लाल मिर्च लिपटी आम की डाल जिसे 'डारा मिरी' कहा जाता था, उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में भूमकाल का संदेश प्रसारित किया गया। फरवरी 1910 में पूरे बस्तर में एक साथ भूमकाल का आगाज गुंडाधुर के संगठन कौशल और पक्की योजना का ही परिणाम था। आंदोलन की शुरुआत पुलिस चौकियों और सरकारी कार्यालयों पर हमले व बाजारों की लूट के रूप में हुई। देखते ही देखते, आंदोलनकारियों ने बस्तर के प्रमुख शहर जगदलपुर को छोड़ शेष बस्तर के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। अंग्रेज सिपाहियों और आजादी के मतवालों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई, जिसमें तीर-धनुष और फरसा-भाला से लड़ने वाले आदिवासियों ने ब्रिटिश शासक के बंदूकधारी सिपाहियों को भागने पर मजबूर कर दिया। गुंडाधुर के अस्तित्व को लेकर अंग्रेजों की कोई भी राय रही हो, लेकिन बस्तर का आदिवासी समाज पूरी आस्था के साथ आज भी उन्हें अपना नायक मानता है। बस्तरवासी गुंडाधुर की याद में भूमकाल दिवस मनाते हैं।

यूपी को गांधी परिवार से मुक्त करेगी भाजपा

अजय कुमार

भारतीय जनता पार्टी देश को कांग्रेस मुक्त भले नहीं कर पाई हो लेकिन उत्तर प्रदेश को गांधी मुक्त बनाने की और उसके कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेताओं को लगता है कि ऐसा मोदी-योगी के कुशल नेतृत्व में होने जा रहा है। ऐसा कैसे होगा? यह समझना मुश्किल नहीं है। एक तरफ इस बात की प्रबल संभावना है कि बीजेपी के लिये लगातार मुसीबत साबित हो रहे राहुल गांधी के चचेरे भाई और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, वहीं उनकी माता मेनका गांधी को उम्र दराज होने के कारण लोकसभा से साइड लाइन करने की तैयारी की जा रही है। मेनका गांधी और वरूण गांधी अब बीजेपी के लिये अनुपयोगी हो गये हैं। बीजेपी इन दोनों नेताओं को यह सोच कर पार्टी में लाई थी कि वरूण गांधी के जरिये वह सोनिया और राहुल गांधी को सियासी आईना दिखायेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं उलटे वरूण गांधी बीजेपी और पीएम मोदी के लिए ही सिरदर्द बन गये। पूरे कार्यकाल के दौरान वरूण गांधी केन्द्र की मोदी सरकार के कामकाज की आलोचना में लगे रहे, जबकि राहुल गांधी के खिलाफ मुंह तक नहीं खोला। इसी के चलते वरूण का टिकट कटना तय है। यदि ऐसा हुआ तो बीजपी गांधी मुक्त हो जायेगी।

बात प्रदेश को गांधी मुक्त करने की कि जाये तो आज की तारीख में यूपी में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली में दिखाई दे रही है। बाकी जगह वह सिमट चुकी है। राहुल गांधी को तो 2019 में ही बीजेपी ने अमेठी से हार का स्वाद चखा कर, ना केवल अमेठी बल्कि प्रदेश से बाहर कर दिया है। अब बीजेपी की मंशा रायबरेली को सोनिया मुक्त करने की है। इसके लिए पिछले पांच सालों में बीजेपी ने सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में काफी मेहनत की है। बीजेपी को जिसका फल आगामी लोकसभा चुनाव में मिलता दिख रहा है। रायबरेली में सोनिया गांधी की स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं रह गई है जितनी पहले हुआ करती थी। यहां से प्रियंका वाड्रा के भी चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। बीजेपी दोनों ही दशा में गांधी परिवार से मुकाबला करने के लिए कमर कसे हुए है। बीजेपी रायबरेली में कांग्रेस की उन दोनों संभावनाओं को खत्म कर देना चाहती है जिसके अनुसार रायबरेली में सोनिया गांधी की जगह प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ाये जाने की चर्चा राजनीति के गलियारों में चल रही है। बीजेपी सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा दोनों को ही अब यहां पर पैर जमाये रखने का मौका नहीं देना चाहती है।

दरअसल, प्रियंका वाड्रा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से भले ही अपने को समेट लिया हो लेकिन रायबरेली में उनकी राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं, इसीलिए राजनीति के जानकार प्रियंका वाड्रा के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इंकार नहीं करते हैं। यदि सोनिया गांधी राजनीतिक दबाव के चलते रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो प्रियंका वाड्रा के लिए अमेठी दूसरी सबसे सुरक्षित सीट रह सकती है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यहां से राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने काफी मेहनत की है। इसलिए हाल फिलहाल राहुल गांधी की तो दाल अमेठी में नहीं गलती दिखाई दे रही है वहीं प्रियंका वाड्रा को भी यहां से चुनाव लड़ने से पहले सौ बार सोचना होगा। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 48 सालों तक उत्तर प्रदेश की अमेठी विकास से वंचित रही, जबकि लोकसभा में इसका प्रतिनिधित्व गांधी परिवार के लोग करते रहे थे। स्मृति ईरानी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ही इस संसदीय क्षेत्र का विकास होना शुरू हुआ। ईरानी ने कहा कि राजमोहन गांधी ने गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें गांधी परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए नकली गांधी बुलाया गया था। मेनका गांधी और शरद यादव को भी अपमानित किया गया था। शरद यादव से कहा गया कि वह जाकर गाय चराएं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में यदि अमेठी के बाद रायबरेली में भी गांधी परिवार का उम्मीदवार हार जाता है तो यूपी पूरी तरह से गांधी परिवार मुक्त हो जाएगा। सोनिया की हार की संभावनाओं से इसलिए इंकार नहीं किया जाता क्योंकि पिछले 5 सालों से वह रायबरेली से पूरी तरह से कटी हुई हैं, जबकि भाजपा ने यहां काफी मेहनत की है।

बात अमेठी और रायबरेली से आगे की कि जाये तो बीजेपी का सबसे अधिक फोकस यूपी पर ही है। मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी लगातार प्लान बना रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी करीब डेढ़ दर्जन सांसदों के टिकट काट सकती है वहीं जातीय समीकरणों को देखते हुए कई नए चेहरों पर भी मंथन किया जा रहा है। इसी के साथ यूपी की हारी सीटों को लेकर भी बीजेपी ने अहम रणनीति बनाई है। यूपी में जिन सीटों पर नए चेहरों को लेकर चर्चा है उनमें पहला नाम सहारनपुर का है जहां से बीजेपी के राघव लखनपाल की जगह नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही बिजनौर सीट पर कुंवर भारतेंद्र सिंह की जगह नया जाट चेहरा आगे किया जा सकता है। नगीना सीट से यशवंत सिंह की टिकट पर सस्पेंस है। मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश कुमार की जगह नया चेहरा संभव है। संभल सीट से परमेश्वर लाल सैनी की टिकट पर और अमरोहा से कंवर सिंह तंवर की टिकट पर संशय है। इसी तरह से मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य की जगह नया उम्मीदवार उतारा जा सकता है। वहीं रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह और अंबेडकर नगर से मुकुट बिहारी वर्मा, श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा, लालगंज से नीलम सोनकर, घोसी से हरिनारायण राजभर का टिकट कट सकता है। उधर गाजीपुर से 2019 में बीजेपी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी रहे मनोज सिन्हा की जगह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सीट दी जा सकती है। जौनपुर से कृष्ण प्रताप सिंह की जगह निषाद पार्टी के प्रत्याशी को यहां से लड़ाया जा सकता है। यह वह बीजेपी नेता हैं जो 2019 में लोकसभा चुनाव जीत नहीं सके थे।

बात भाजपा के मौजूदा सांसदों, जिनका टिकट कटने की उम्मीद है उनकी की जाये तो उसमें कानपुर से सत्यदेव पचैरी (76 साल), बहराइच से अक्षयवर लाल (77), बाराबंकी से उपेंद्र सिंह, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह (73), मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल (73), हाथरस से राजवीर दिलेर, मथुरा से हेमामालिनी (75), बरेली से संतोष गंगवार (75), फिरोजाबाद से चंद्रसेन जादौन (73) का और कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी, पीलीभीत से वरुण गांधी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी और बदायूं से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या की बेटी संघमित्रा मौर्य का भी टिकट कटना तय लग रहा है।

लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि यूपी में बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक 80 सीटें हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी कि बात की जाये तो 2019 में यूपी की 80 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में एनडीए में बीजेपी और अपना दल (एस) एक साथ मिलकर लड़े थे और एनडीए का 51.19 प्रतिशत वोट शेयर रहा था। जिसमें बीजेपी के खाते में 49.98 प्रतिशत और अपना दल (एस) को 1.21 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। वहीं महगठबंधन (बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल) को 39.23 प्रतिशत वोट शेयर मिला था।

आज का इतिहास

1912 फ्रेंच सीनेट ने मोरक्को समझौते को मंजूरी दी।
1917 जोहान्ना वेस्टरडिच नीदरलैंड की पहली महिला प्रोफेसर बनी।
1930 वियतनाम में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की आशा में असफल वियतनाम क्रोक डैन डांग ने येन बाई म्युटिनिन को लॉन्च किया।
1936 दूसरा इटालो-एबिसिनियन युद्ध-अम्बा अरदम की लड़ाई शुरू हुई और नौ दिनों के बाद इटली के लिए एक निर्णायक रणनीति की जीत और लगभग पूरी इथियोपियाई सेना के एक लड़ाई बल के रूप में निष्प्रभावी हो गई।
1939 स्पैनिश गृहयुद्ध-राष्ट्रवादियों ने अपने युद्ध का समापन कैटेलोनिया से किया और फ्रांस के साथ सीमा को सील कर दिया।
1959 अमेरिका के सेंट लुईस में तूफान से 19 की मौत हुई और 265 घायल हुए।
1961 कनाडा में नियाग्रा जलप्रपात की पनबिजली परियोजना से बिजली का उत्पादन शुरु हुआ।
1962 रॉय लिचेंस्टीन की पहली एकल प्रदर्शनी खुली, और इसमें लुक मिक्की को शामिल किया गया, जिसमें बेन-डेडोट्स, भाषण गुब्बारे और कॉमिक इमेजरी सोर्सिंग के अपने पहले रोजगार को चित्रित किया गया था, जिसके लिए वह अब जाना जाता है।
1962 एफबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए एक सोवियत जासूस रुडोल्फ एबेल का गैरी पॉवर्स के लिए आदान-प्रदान किया गया था, जो कि दो साल पहले सोवियत हवाई क्षेत्र में गोली मार दी गई थी।
1991 मुक्केबाजी की दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ी रहे माइक टाइसन को बलात्कार का दोषी पाकर 6 साल की सजा सुनाई।
1993 माइकल जैक्सन ने एबीसी पर ओपरा विनफ्रे के हवा में बात की और 39.3 रेटिंग / 56 मिलियन के बारे में 90 मिलियन लोगों के आश्चर्यजनक रूप से आकर्षित किया।
1996 आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने पहली बार शतरंज में गैरी कास्परोव को हराया।
1996 आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीब ब्लू ने शतरंज में वर्ल्ड चैम्पियन मैरी कास्परोव को पहली बार हराया।
1997 इस दिन 5 वें वार्षिक ESPY पुरस्कार हुए।
2003 नामीबिया ने पहला अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच खेला।
2006 इटली के ट्यूरिन में 20 वा शीतकालीन ओलंपिक खेल शुरू किया गया।

उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर हंगामा क्यों

अवधेश कुमार

उत्तराखंड सरकार द्वारा यूनिवर्सल सिविल कोड (यूसीसी) या समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करना ऐतिहासिक घटना है। अभी तक सिर्फ गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि और प्रकृति अलग है। वहीं, संविधान को मंजूरी मिलने के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर जिस समान नागरिक संहिता की मांग की जा रही थी, उस दिशा में कदम बढ़ाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सत्तारूढ़ भाजपा समान नागरिक संहिता की बात तो करते थे, लेकिन उसकी रूपरेखा सामने नहीं थी। पहली बार किसी राज्य की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता का प्रारूप सामने रखा है। इसके बाद अन्य भाजपा शासित राज्यों और केंद्र की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावना मजबूत हुई है।

विरोधियों की बात मानें तो यह भाजपा की अपना अजेंडा लागू करने की कोशिश है, जिसका मकसद एक धर्म और उसकी मान्यताओं के अनुरूप समाज और व्यवस्था का निर्माण है। भाजपा के अजेंडा की बात समझ में आती है, लेकिन इस कदम को किसी धर्म, पंथ या मजहब से जोड़ना किसी दृष्टिकोण से तथ्यपरक नहीं कहा जा सकता। कुल 192 पृष्ठ और 392 धाराओं वाली इस संहिता में कहीं नहीं लिखा है कि फलां धर्म या पंथ के लोग ऐसा नहीं कर सकते या वैसा कर सकते हैं। किसी भी धार्मिक, पंथिक, सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं, रीति-रिवाजों पर इसका असर नहीं होगा। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिससे खान-पान, पूजा-पाठ, इबादत, वेशभूषा, रहन- सहन पर कोई प्रभाव पड़े। इसी तरह कोई किस तरीके से शादी करे, शादी-विवाह-निकाह कौन कराए, इसके भी प्रावधान नहीं हैं। जाहिर है, समान नागरिक संहिता को लेकर अभी तक किया

गया प्रचार झूठा साबित हुआ है कि इससे हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्म के लोग अपनी परंपरा, रीति-रिवाज के अनुसार शादी-विवाह या अन्य कर्मकांड नहीं कर पाएंगे। वास्तव में यह प्रगतिशील व्यवस्था और समाज निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कोई प्रगतिशील व्यवस्था किसी की धार्मिक-सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं और रीति-रिवाजों को प्रतिबंधित करने या उन पर अंकुश लगाने जैसा विधान स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसी कट्टरवादी संकीर्ण सोच के लिए सभ्य समाज में स्थान नहीं हो सकता। इसलिए मुस्लिम संगठनों, मजहबी नेताओं या राजनीतिक दलों का विरोध केवल विरोध के लिए है। सारे विरोध और आरोप तब के हैं जब सामने ड्राफ्ट नहीं था। अब तो बात केवल प्रावधानों पर होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता जीवन के केवल पांच क्षेत्रों- विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार और गोद लेना या दत्तकग्रहण ङ्क के लिए है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के चार खंड हैं- विवाह और विवाह विच्छेद या तलाक, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध या लिव-इन रिलेशनशिप और विविध। इसमें विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 व लड़के की न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है तो बहु विवाह और बाल विवाह का निषेध है। सगे रिश्तेदारों से संबंध निषेध तो है पर यह उन पर लागू नहीं होगा जिनकी प्रथा या रूढ़ियां ऐसे संबंधों में विवाह की अनुमति देती हैं।

इस क` ज्यादातर प्रावधान सभी धर्मों की महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता पर आधारित न्यायपूर्ण प्रगतिशील समाज के निर्माण का ही संदेश देते हैं। उदाहरण के लिए, पुरुष और महिला दोनों को तलाक के समान अधिकार होंगे तो पति या पत्नी में से किसी के जीवित रहने पर दूसरे विवाह की अनुमति नहीं होगी। किसी को एक से अधिक विवाह करना हो या पुरुषों के समान महिलाओं को तलाक के अधिकार देने से समस्या हो तो उसे जरूर समान नागरिक संहिता से दिक्कत होगी। तलाक की याचिका लंबित रहने पर भरण-पोषण और बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित प्रावधानों पर उन्हें ही आपत्ति हो सकती है जो सामाजिक न्याय नहीं चाहते। धार्मिक मान्यताएं चाहे जो भी हों, किसी व्यक्ति को पुनर्विवाह या तलाक के मामले में स्वच्छंदता नहीं दी जा सकती। समान नागरिक संहिता की प्रगतिशील प्रकृति का एक प्रमाण संपत्ति में पुरुषों के समान महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना है। इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि किसी भी परिवार के जीवित बच्चे, पुत्र या पुत्री संपत्ति में बराबर के अधिकारी होंगे।

हालांकि लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रावधानों से भाजपा एवं संघ परिवार के अंदर थोड़ी असहजता भी महसूस की जा रही है। लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण न कराने पर दंड, उस अवधि में पैदा होने वाले बच्चों को वैध संतान की मान्यता और पुरुष द्वारा लिव-इन की महिला को छोड़ने पर उस महिला को भरण-पोषण पाने के अधिकार जैसे प्रावधानों से आशंका पैदा हुई है कि ऐसे संबंध विस्तारित हो सकते हैं। कुल मिलाकर समान नागरिक संहिता स्वतंत्रता के बाद समाज के सभी हिस्सों ङ्क पुरुष, स्त्री, बच्चों ङ्क के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है। यह प्रगतिशील लोकतांत्रिक और परस्पर सम्मान पर आधारित समाज के निर्माण के सपने को पूरा करने का विधान है। धामी सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति रंजना देसाई समिति ने इस पर विस्तार से कार्य किया है। अन्य देशों की संहिताओं, संविधान सभा में हुई बहस आदि का अध्ययन किया गया, लोगों से सुझाव मांगे गए और जगह-जगह बैठकें की गईं। समिति को ढाई लाख से अधिक सुझाव? प्राप्त हुए।

संविधान निर्माण के समय से ही समान नागरिक संहिता पर बहस चलती रही है। इसके विरोध का कारण झूठ, दुष्प्रचार या मजहब के नाम पर गैर-मजहबी पुरुषवादी व्यवस्था को बचाए रखने की मानसिकता रही है। इसे संघ और भाजपा का अजेंडा बताने वाले भूल रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों व समाजवादियों के घोषित अजेंडा में समान नागरिक संहिता लागू करना शामिल रहा है। डॉ. राम मनोहर लोहिया इसके पैरोकार थे। विडंबना देखिए कि आज कम्युनिस्टों और समाजवादियों की आवाज भी इसके विरुद्ध है। इसे देखकर लगता है कि विरोध के पीछे ईमानदारी और नैतिकता नहीं है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता देने की अपेक्षा की गई है और अब उस अपेक्षा को पूरा करने की शुरुआत हो गई है।

कानून और राजनीति में उलझता आरक्षण

अमिताभ श्रीवास्तव

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के माथे पर गुलाल लगाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी मांगें पूरी करने का लिखित आश्वासन तो दे दिया, मगर सवाल आज भी वहीं और वैसे ही हैं, जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है, जिसमें आरक्षण की मांगों को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। किंतु समूचे परिदृश्य में कोई भी पूरी तौर पर आश्वस्त नहीं है। यहां तक कि जरांगे भी क्रमिक भूख हड़ताल को जारी रखे हैं और आगे भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एकजुट होकर आंदोलन करने जा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं न कहीं मराठा आरक्षण से उसका हक मारा जाएगा। आखिर बार-बार नई उलझन और हर बार उसे नए प्रकार से सुलझाने का सिलसिला कब तक चलेगा। बीते साल अगस्त माह से मराठवाड़ा में कुनबी समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे जरांगे ने जालना जिले की घनसावंगी तहसील के अंतरवाली सराटी गांव से मुंबई तक का लंबा सफर तय किया। उन्होंने लाठीचार्ज से लेकर फूलों की वर्षा तक देखी। एक गैरराजनीतिक व्यक्ति ने महाराष्ट्र सरकार को अपने गांव बुलाकर अपनी मांगों को पूरा कराने से लेकर मुंबई पहुंच कर अपने आंदोलन में मुख्यमंत्री शिंदे को बुलाकर ही दम लिया। उनकी महागठबंधन सरकार ने जरांगे की सभी मांगों को स्वीकार किया और एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश पर वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ तीन घंटे चर्चा भी हुई। इतना सब कुछ होने के बावजूद मराठा आरक्षण को लेकर संशय बना ही हुआ है। राज्य सरकार कह रही है कि कुनबी के रूप में पहचाने गए 54 लाख व्यक्तियों को कुनबी प्रमाण-पत्र जल्द ही प्रदान किए जाएंगे। फिर भी भरोसा तब तक नहीं हो पाएगा, जब तक कि आरक्षण प्रत्यक्ष रूप में नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ, जहां धनगर समाज और मुस्लिम भी आरक्षण की मांग करते चले आ रहे हैं तो उन्हें भी कुछ प्रेरणा मराठा आरक्षण आंदोलन दे ही रहा है। धनगर आरक्षण कृति (कार्य) समिति के नेतृत्व में धनगर समाज अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है। राज्य की आबादी में धनगरों की हिस्सेदारी नौ प्रतिशत तक है। इस समाज को धनगड़ के रूप में देश के अनेक भागों में आरक्षण का पात्र माना गया है। महाराष्ट्र में मुद्रण संबंधी त्रुटि के कारण समुदाय को धनगर के रूप में सूचीबद्ध किया गया. परिणामस्वरूप, समुदाय को एसटी श्रेणी से बाहर कर दिया गया। राज्य में प्रकाश शेंडगे, राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष महादेव जानकर और गोपीचंद पडलकर जैसे नेताओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आंदोलन हो चुके हैं। पिछले दिनों अहमदनगर जिले में आमरण अनशन को सरकार ने आश्वासन देकर तुड़वाया था। इसी बीच, राज्य मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री छगन भुजबल जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज का नेतृत्व करते हैं, वह अपनी सरकार से नाराज हैं। वह कहते हैं कि मराठा आरक्षण के नाम पर कुछ भी हो रहा है, जिसे वह भीड़तंत्र के सामने आत्मसमर्पण से अधिक कुछ नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि मराठा आरक्षण के लिए अध्यादेश ओबीसी और वीजेएनटी (विमुक्त जाति और घुमंतू जनजातियों) के अधिकारों पर अतिक्रमण है और जिसके लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश करने के वास्ते लाखों हलफनामे जमा किए जा रहे हैं। वह अब ओबीसी समाज के लिए तीन विकल्प - मराठा कोटा पर मसौदा अधिसूचना के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और अपने साथ हो रहे अन्याय को लोकतांत्रिक मंचों के माध्यम से उजागर करना बता रहे हैं। यह साफ कर रहा है कि एक तरफ जहां मराठा समाज में खुशी की लहर है तो वहीं ओबीसी समाज लामबंद होने को तैयार है। कारण साफ है कि सरकार आरक्षण को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। उसके पास आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं है. मुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बार-बार कह रहे हैं कि ओबीसी समाज के आरक्षण को प्रभावित किए बिना वे मराठा समाज को आरक्षण देंगे। यदि आरक्षण का इतिहास देखा जाए तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पश्चिमी यूपी का किला फतह!

अमित शर्मा

चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का एलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना रालोद नेता जयंत सिंह चौधरी को अपने पाले में लाने की बड़ी रणनीति हो सकती है। रालोद अपने नेता के लिए लगातार भारत रत्न देने की मांग कर रही थी। कहा जा रहा है कि दोनों दलों के बीच जयंत तो एनडीए खेमे में लाने के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की भी एक शर्त रखी गई थी, जिसे भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया था। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की भी घोषणा की थी। पिछड़े-दलितों के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के तुरंत बाद ही बिहार की राजनीति में बड़ा

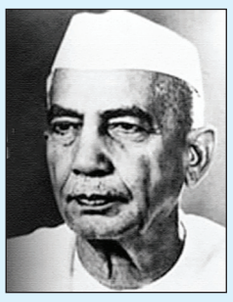

बदलाव आया था। नीतीश कुमार ने इस घोषणा के बाद ही भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए में वापसी करने की घोषणा की थी। भाजपा को इसका बिहार में चुनावी लाभ मिल सकता है। अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा कर भाजपा ने पश्चिम के किले को अभेद्य बनाने की कोशिश की है। ध्यान देने की बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिम में ही सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने की घोषणा की है। वे दक्षिण भारत से आते हैं। जिस तरह भाजपा लगातार दक्षिण भारत की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करती रही है, माना जा रहा है कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर भी केंद्र ने अपने मिशन साउथ को मजबूती देने का काम किया है। चूंकि वे कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शामिल थे, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस ने उन्हें पूरा सम्मान नहीं दिया, यह कांग्रेस को भी असहज करने की रणनीति हो सकती है। भाजपा को इससे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लाभ मिल सकता है। वह यह दावे कर सकती है कि दक्षिण के जिस बड़े नेता का कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया, भाजपा ने उन्हें भी पूरा सम्मान देने की कोशिश की है। एनडीए को इससे लाभ हो सकता है। चौधरी चरण सिंह के साथ-साथ किसानों के बड़े शुभचिंतक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के मामले में स्वामीनाथन का अध्ययन आज भी सरकारों को दिशा दिखाने के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा कर भी केंद्र सरकार ने किसानों का दिल जीतने की कोशिश की है।

जयंत चौधरी पर डोरे क्यों डाल रही भाजपा?

अंकित सिंह

लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब से लगभग 1 महीने के भीतर ही चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। इसी के साथ जोड़-तोड़ की भी राजनीति देखने को मिल रही है। बिहार और झारखंड में सियासी हलचल के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी बनती दिख रही है। इसका बड़ा कारण राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी फिलहाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। बावजूद इसके उनके भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर अटकलें काफी जोरों पर है। यहां तक दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। खबर यह भी है कि भाजपा की ओर से जयंत चौधरी के समक्ष चार सीटों की पेशकश की गई है।

अटकलों पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि मैं जयंत (सिंह) को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वे धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। भाजपा सिर्फ मीडिया का इस्तेमाल कर गुमराह कर रही है। वे (रालोद) इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे और भाजपा को हराएंगे। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी किसानों के खिलाफ काम कर रही है और जिस तरह से बीजेपी ने हमारे पहलवानों का अपमान किया है, मुझे नहीं लगता कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी कोई ऐसा कदम

उठाएंगे जिससे हमारे किसानों को सीधा नुकसान होगा। अपना दल पार्टी की अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मैंने मीडिया रिपोर्टें पढ़ी हैं जिनमें कहा गया है कि रालोद एनडीए परिवार में शामिल होने जा रहा है। मैं अपनी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करती हूं। रालोद और भाजपा के बीच सीटों के बंटवारे की जानकारी मुझे नहीं है। मैं यूपी या कहीं और से किसी भी पार्टी के एनडीए में शामिल होने का स्वागत करूंगी, ताकि एनडीए मजबूत हो। बीजेपी सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि ढ्ढह्लष्ठढ्ढ गठबंधन की न तो नीति ठीक है और न ही नियत। यह गठबंधन अतीत की बात बनता जा रहा है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें तो यहां जाट और मुस्लिम वोट का बोलबाला रहा है। क्षेत्र की कुल 27 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 2019 में 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। आठ पर बसपा-सपा गठबंधन को जीत मिली थी। हालांकि, भाजपा को अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए जाट वोटरों के समर्थन की जरूरत रहती है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि इधर मुस्लिम वोटो का बड़ा आधार है जो भाजपा के पक्ष में नहीं आता। जिन आठ सीटों पर पार्टी को 2019 में हार मिली थी वहां हर हाल में इस बार जीत हासिल करने की कवायद चल रही है ताकि 400 पार का आंकड़ा पूरा किया जा सके। 2014 में एनडीए ने जहां उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की थी तो वही 2019 में आंकड़ा मात्र 64 का रह गया था। यही कारण है कि भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी पर डोरे डाल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट लैंड भी कहा जाता है जहां उनकी आबादी 18ह्ल है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट भाजपा गठबंधन के पक्ष में खड़े होते दिखाई देंगे तभी हरियाणा और राजस्थान में भी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। जयंत को अपने पाले में करने के साथ ही भाजपा इंडिया गठबंधन पर मनोवैज्ञानिक दवाब बनाने में कामयाब रहेगी।

पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ते हुए जयंत चौधरी को अब तक कुछ खास सफलता नहीं मिली है। राष्ट्रीय लोक दल 2014 और 2019 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शून्य सीटों पर सिमट गई थी। 2014 में तो उसे सिर्फ 0.9ह्ल वोट मिला था। हालांकि 2019 में इसमें वृद्धि देखी गई। बावजूद इसके दोनों ही चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल को एक भी सीट नहीं मिल सकी। 2014 के चुनाव में आरएलडी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जयंत चौधरी मथुरा से, बागपत से अजीत सिंह, अमरोहा से राकेश टिकैत जैसे दिग्गज नेताओं को हार मिली थी। यही कारण है कि 2024 में राजनीतिक भविष्य को देखते हुए जयंत को सोचना पड़ रहा है। जयंत को पता है कि राम मंदिर की लहर है और जाट समाज में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। जयंत को यह भी पता है कि जब सपा-बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई तो इस बार तो सिर्फ सपा के साथ गठबंधन में इसकी उम्मीद करना कितना ठीक रहेगा? इसके अलावा जयंत को जिन सीटों की पेशकश की गई है, उनमें कैरना, बागपत, मथुरा और अमरोहा है। कैराना, बागपत और मथुरा में बीजेपी का लगातार दो बार से कब्जा है। ऐसे में जयंत को भी पता है कि इन चार सीटों में से कम से कम तीन पर तो उनकी पार्टी को जीत मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जयंत के करीबियों को विधान परिषद के रास्ते सेट किया जा सकता है। आरएलडी नेताओं को योगी सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है।

मोदी ने किया नेहरू परिवार मुक्त संसद की ओर इशारा?

अजय सेतिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में दिए गए भाषण में कुछ बातें तो एक दम स्पष्ट हैं, लेकिन कुछ बातों को डिकोड करने की जरूरत है। खासकर वे बातें जो उन्होंने कांग्रेस और नेहरू परिवार के बारे में उनका नाम लिए बिना कही हैं। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाया था, लोकसभा में सिर्फ 44 सीटें देकर देश की जनता ने कांग्रेस को ऐसी स्थिति में पहुंचा भी दिया था। इस बार उन्होंने नेहरू परिवार को सदन से दर्शक दीर्घा में पहुँचाने की बात कही है।

इसका मतलब यह है कि नेहरू परिवार की अमेठी सीट से राहुल गांधी को हराने के बाद मोदी का संकल्प परिवार की रायबरेली सीट से कांग्रेस को हराना है। ठीक इसी समय पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वह गांधी परिवार के अलावा अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करे। जिस गांधी के कारण इस परिवार के लोग अपने नाम में गांधी लगाते हैं, रायबरेली उस फिरोज गांधी की लोकसभा सीट है। इस सीट का नेहरू परिवार से कोई ताल्लुक नहीं। 1952 और 1957 में इस सीट से फिरोज जहांगीर गांधी जीते थे। 1960 में फिरोज गांधी के देहांत के बाद उपचुनाव में कांग्रेस के आरपी सिंह और बाद में 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस के ही बैजनाथ कुरील जीते। 1967 में फिरोज गांधी की पत्नी और जवाहर लाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने अपने पति की सीट पर चुनाव लड़ा। 1971, 1977 और 1980 में भी इंदिरा गांधी ने ही रायबरेली से चुनाव लड़ा। 1977 के चुनाव में राज नारायण से हार जाने के बाद इंदिरा गांधी कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट से उप चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंची थी। क्योंकि 1977 में इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई थी, इसलिए एहतियात के तौर पर 1980 में वह रायबरेली के साथ साथ कर्नाटक की मेढक सीट से भी चुनाव लड़ी। दोनों सीटों से जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने रायबरेली से इस्तीफा दे दिया। 1980 का उप चुनाव और 1984 का आम चुनाव नेहरु परिवार के ही अरुण नेहरु ने जीता।

1989 में रायबरेली सीट इंदिरा गांधी की मौसी शीला कौल को दे दी गई, जो लगातार दो बार वहां से जीती। लेकिन 1996 में भाजपा के अशोक सिंह ने यह सीट कांग्रेस से छीन ली थी, वह 1998 में भी वहां से जीते। इसलिए सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने से डर रही थीं। उन्होंने सतीश शर्मा को रायबरेली से चुनाव लड़वाया और खुद अपने देवर और अपने पति के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़ी, लेकिन आश्वस्त नहीं थी कि वह अमेठी में जीत ही जाएँगी, इसलिए वह अमेठी के साथ साथ कर्नाटक की उस बेल्लारी सीट से भी चुनाव लड़ी, जो आज़ादी के बाद कांग्रेस कभी नहीं हारी थी। गांधी परिवार हमेशा सुरक्षित सीटें ढूंढता रहा है। जब जब आशंका हुई इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दो दो सीटों से चुनाव लड़ते रहे। 1999 में रायबरेली से राजीव गांधी के करीबी सतीश शर्मा को चुनाव लड़वाया गया, लेकिन 2004 में अमेठी सीट राहुल गांधी को देकर सोनिया गांधी खुद अपने ससुर फिरोज गांधी की सीट रायबरेली चली गई।

पिछले चार चुनाव सोनिया गांधी रायबरेली से ही जीत रही हैं। अपनी उम्र और बीमारी की वजह से इसबार वह चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उन्हीं के बारे में बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह राज्यसभा में आने का रास्ता खोज रही हैं। अमेठी के बाद मोदी का इस बार का टारगेट रायबरेली है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह परिवार जल्द ही दर्शक दीर्घा में दिखेगा। जबकि गांधी परिवार रायबरेली सीट को बचाए रखने के लिए वहां से राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ाने पर विचार कर रहा है। एक विचार यह चल रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ें और प्रियंका वाड्रा को उनके चाचा संजय गांधी, पिता राजीव गांधी और भाई राहुल गांधी की सीट अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने उतार कर अमेठी वापस छिनी जाए। अब अमेठी में स्मृति ईरानी का मुकाबला करना राहुल गांधी के बस में नहीं है। क्योंकि स्मृति ईरानी ने अपनी सीट को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जब अजय राय ने कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, तो उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कह दिया गया था।

राहुल गांधी के बारे में ही मोदी ने अपने भाषण में कहा कि वह पिछली बार सीट बदल कर लोकसभा में पहुंच गए थे, इस बार फिर सीट बदलने की सोच रहे हैं। मोदी ने लोकसभा में यह बात बिना आधार के नहीं कही। कांग्रेस सर्कल में चर्चा है कि राहुल गांधी ने क्योंकि पीएफआई पर बैन का विरोध नहीं किया, इसलिए वह वायनाड से जीत नहीं सकते। वायनाड में पीएफआई समर्थक मुस्लिमों की भरमार है, जिन्होंने पिछली बार राहुल का खुल कर समर्थन किया था। केरल की वायनाड सीट में हिन्दू 49.48 प्रतिशत हैं, मुस्लिम 29 प्रतिशत और 21 प्रतिशत ईसाई हैं। बचे खुचे आधा प्रतिशत जैन सिख आदि हैं। पिछली बार राहुल गांधी मुसलमानों के एक तरफा वोटों और ईसाईयों के समर्थन से जीत गए थे। ऐसा नहीं कि उन्हें हिन्दू वोट नहीं मिला था, उन्हें हिन्दू वोट भी मिला था, लेकिन कम। इस बार वायनाड की तस्वीर पूरी तरह बदली हुई है। वायनाड के करीब 50 प्रतिशत हिन्दू श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर बनने से गदगद हैं। वायनाड के साथ भगवान राम का गहरा रिश्ता भी माना जाता है। जहां तक ईसाई मतदाताओं का सवाल है, तो 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाक़ात के बाद परिस्थितियां बदली हैं। केरल के ईसाई नेता पीसी जार्ज ने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया है। जार्ज ने भाजपा ज्वाइन करने से पहले केरल के विभिन्न चर्चों के प्रतिनिधियों से चर्चा की थी। चर्चों की सहमति के बाद ही उन्होंने भाजपा ज्वाईन की।

केरल में हिन्दू-ईसाई का नया समीकरण बन रहा है, जो सोनिया गांधी की कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि केरल के ईसाईयों को कांग्रेस की रहनुमाई वाले यूडीएफ का समर्थक माना जाता रहा है। लेकिन लव जिहाद, धर्मांतरण और यूडीएफ में मुस्लिम लीग के बढ़ते दबदबे के कारण ईसाई भाजपा की तरफ झुक रहे हैं।

केरल के चर्चों के बिशपों ने भी भाजपा के साथ संपर्क बढाया है। क्रिसमस के मौके पर बिशपों की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाक़ात इसी कड़ी में हुई थी। कांग्रेस के टॉम वडकम और अनिल एंटनी भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसलिए मुस्लिम समर्थन कर भी दें, तो भी हिन्दू ईसाई समीकरण ही राहुल गांधी को वायनाड से हरा सकता है। नेहरू गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश की दो सीटों के अलावा कर्नाटक से भी गहरा रिश्ता रहा है। इंदिरा गांधी कर्नाटक की चिकमंगलूर से और सोनिया गांधी कर्नाटक की बेल्लारी सीट से एक एक बार चुनाव जीत चुकी हैं। इसलिए ज्यादा संभावना यही है कि सोनिया गांधी कर्नाटक से राज्यसभा में आ सकती हैं। राहुल गांधी न खुद को अमेठी में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, न वायनाड में। इसलिए ज्यादा संभावना यही है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेहरू परिवार मुक्त संसद के एजेंडे से भयभीत राहुल गांधी रायबरेली के साथ साथ कर्नाटक की किसी सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं।

सर्दियों पाना चाहती हैं स्टाइलिश लुक तो ट्राई करें जैकेट स्टाइल सूट, फंक्शन में दिखेंगी सबसे अलग

अगर आप सर्दियों में अपने कलेक्शन में जैकेट स्टाइल सूट रखना चाहती हैं, तो इसमें आप स्टाइलिश और कंफर्टेबल महससू कर सकेंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्टाइलिश लुक पाने के लिए किस तरह के सूट कैरी कर सकती हैं।

सर्दियों में मौसम में अक्सर हम सभी ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सर्दियों में कंफर्टेबल रहने के लिए हम अलग-अलग जगहों पर जाकर अपने लिए कपड़ों को ढूढ़ते हैं। जिससे कि उनको स्टाइल करने पर हम सबसे सुंदर और अलग नजर आ सके। ऐसे में अगर आप सर्दियों में अपने कलेक्शन में जैकेट स्टाइल सूट रखना चाहती हैं, तो इसमें आप स्टाइलिश और कंफर्टेबल महससू कर सकेंगे। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे आप स्टाइलिश लुक पाने के लिए किस तरह के सूट कैरी कर सकती हैं।

जैकेट स्टाइल सूट विद प्लाजो पैंट

अगर आपको भी पैंट सूट पहनना अच्छा लगता है, तो आप जैकेट वाले आउटफिट्स को ट्राई कर सकते हैं। बता दें कि इस जैकेट स्टाइल सूट को पैंट सेट के साथ पेयर कर सकते हैं। बल्कि कई बार प्लाजो पैंट के साथ जैकेट स्टाइल सूट अटैच होकर आती है। इसको आप आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसमें आपको कई अच्छे और डिफरेंट स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। इसको वियर करने के बाद आपको बेहद स्टाइलिश लुक मिलेगा। मार्केट में

आपको यह सूट 1000-2000 रुपए तक में आसानी से मिल जाएंगे।

ट्राउजर जैकेट स्टाइल सूट

अगर आप भी सर्दियों में नए तरीके से सूट स्टाइल करना चाहती हैं, तो आप ट्राउजर स्टाइल जैकेट सूट ट्राई कर सकती हैं। इसमें आपको सिंपल से लेकर हैवी डिजाइंस तक मिल जाएंगे। इन सूट्स को आप किसी पार्टी या फंक्शन में स्टाइल कर सकती हैं। वहीं पूजा-पाठ में भी आस इनको स्टाइल कर सकती हैं। मार्केट में आपको 1000-2000 रुपए तक अच्छे डिजाइन वाले सूट मिल जाएंगे।

अनारकली जैकेट सूट

कई लोगों को अनारकली सूट पहनना भी काफी पसंद होता है। ऐसे में आप सर्दियों में जैकेट स्टाइल वाले अनारकली ऑप्शन को ट्राई कर सकती हैं। क्लासी लुक के लिए यह बेस्ट है। इसको स्टाइल करने के बाद आपको अच्छा लुक मिलेगा। आप चाहें तो ज्यादा घेर वाली अनारकली जैकेट सूट ले सकती हैं। आपको मार्केट में इस तरह के सूट में कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप इसमें कलर और डिजाइन पैटर्न खरीद सकते हैं।

काजल खरीदते समय इन बातों का रखें खास ख्याल, इंफेक्शन से बची रहेंगी आंखें

काजल के जरिए आई मेकअप लुक्स को रीक्रिएट किया जा सकता है। वहीं सर्दियों में मौसम में आंखों में काजल लगाना अवॉइड किया जाता है। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जिनको आप काजल खरीदने के दौरान ध्यान में रखें।

हम सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं। वहीं मेकअप में आई लुक का रोल सबसे ज्यादा अहम होता है। वहीं रोजाना मेकअप में अक्सर आंखों सिर्फ काजल लगाया जाना पसंद किया जाता है। हांलाकि काजल के जरिए आई मेकअप लुक्स को रीक्रिएट किया जा सकता है। वहीं सर्दियों में मौसम में आंखों में काजल लगाना अवॉइड किया जाता है।

लेकिन अगर आप भी कुछ बातों का ख्याल रखती हैं, तो किसी भी मौसम में आंखों में काजल अप्लाई कर सकती हैं। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जिनको आप काजल खरीदने के दौरान ध्यान में रखें। ऐसे में आप हर मौसम आंखों में काजल लगाकर अपने लुक को आकर्षक बना सकती हैं।

काजल में ऑयल

पेंसिल काजल का इस्तेमाल करने से यह ड्राइनेस को बढ़ा देता है। लेकिन अगर पेंसिल काजल में ऑयल मौजूद हो, तो इससे आपकी आंखों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसलिए प्रयास करें कि आप ऑयल के लिए नेचुरल पदार्थ वाले प्रोडक्ट को चुनें। क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखों को भी भरपूर मात्रा में पोषण मिलेगा।

काजल पेंसिल में केमिकल

आपको मार्केट कई तरह के काजल के बड़े-बड़े ब्रांड्स आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे में आप अपनी आंखों को आकर्षक बनाने के लिए किसी अच्छे ब्रांड वाले प्रोडक्ट को चुनें। क्योंकि लोकल और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स आपकी आंखों को न सिर्फ ड्राई करेंगे, बल्कि यह आपकी आंखों को कई तरह से नुकसान भी पहुंचा सकता है।

इन बातों का रखें खास ख्याल

आई मेकअप करने के दौरान हाथों के दबाव का कम से कम इस्तेमाल करें। जिससे कि आपकी आंखों को किसी तरह का नुकसान न हो।

आई मेकअप के समय ब्लेंडिंग पर खास ध्यान देना चाहिए, जिससे आपका लुक आकर्षक हो।

अगर आपकी आंखें सेंसिटिव हैं, तो वॉटरलाइन से काजल को थोड़ी दूर रखकर ही इस्तेमाल करना चाहिए।

परफेक्ट लुक के लिए हल्दी फंक्शन में कैरी करें ऐसे ब्लाउज, लुक में लगेंगे चार चांद

अपने लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए फंक्शन के हिसाब से ब्लाउज पहने जाते हैं। लेकिन हल्दी के फंक्शन में ब्लाउज चुनने के दौरान महिलाएं व लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं। ऐसे में आप इस तरह के डिजाइन वाले ब्लाउज कैरी कर सकती हैं।

महिलाएं व लड़कियां साड़ी से लेकर लहंगे तक के साथ कई तरह के ब्लाउज कैरी करती हैं। वहीं रेडीमेड ब्लाउज में भी कई डिजाइंस देखने को मिल जाएंगे। वहीं अपने लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए फंक्शन के हिसाब से ब्लाउज पहने जाते हैं। लेकिन हल्दी के फंक्शन में ब्लाउज चुनने के दौरान महिलाएं व लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं।

ऐसे में अगर आप भी हल्दी लुक को खास बनाने के लिए ब्लाउज के स्टाइलिश डिजाइंस देख रही हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ब्लाउज के ये स्टाइलिश डिजाइंस और उनको स्टाइल करने के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं।

क्रॉप टॉप स्टाइल ब्लाउज

अगर आप भी हल्दी फंक्शन में धोती स्टाइल लुक को कैरी करने की सोच रही हैं, तो आप क्रॉप टॉप स्टाइल वाला ब्लाउज पहन सकती हैं। इसमें स्टाइलिश लुक पाने के लिए दुपट्टे की जगह श्रृग या फिर केप स्टाइल कर सकती हैं। इसके अलावा आप ब्लाउज के लिए बैकलेस डिजाइंस चुन सकती हैं। वहीं इस तरह के ब्लाउज में लेस वर्क भी करवा सकती हैं।

प्लेन ब्लाउज डिजाइन

हैवी वर्क वाली साड़ी या लहंगा स्कर्ट के साथ प्लेन ब्लाउज डिजाइन कैरी कर सकती हैं। इस लुक के साथ आप हैवी डिजाइन वाली ज्वैलरी चुनें। इस तरह से हल्दी के फंक्शन में आपका लुक स्टाइलिश और परफेक्ट नजर आएगा। इस लुक के साथ आप फ्रंट ब्रेड हेयर स्टाइल बना सकती हैं।

मिरर वर्क ब्लाउज

आपको बता दें कि हल्दी लुक में सबसे ज्यादा मिरर वर्क के डिजाइन वाले ब्लाउज को पसंद किया जाता है। वहीं अगर आप बोल्ड लुक पाना चाहती हैं, तो बैक डिजाइन के लिए डोरी लगवा सकती हैं या फिर इसमें लटकन लगवा सकती हैं। शरारा से लेकर साड़ी तक के साथ आप इस तरह के ब्लाउज पहन सकती हैं। वहीं अपने लुक को परफेक्ट बनाने के लिए चांदबाली इयररिंग्स कैरी कर सकते हैं।

मिलेगी लंबी घनी आईलैशेज बस घर पर बनाएं ये जेल

नारियल तेल और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके आईलैश जेल तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप नारियल तेल और एलोवेरा जेल को बराबर मात्रा में लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें।

अक्सर लड़कियां अपनी आईलैशेज को लंबा व घना दिखाने के लिए नकली आईलैशेज का इस्तेमाल करती हैं या फिर अपनी रियल आईलैश पर मस्कारा लगाती हैं। इससे आप कुछ समय के लिए तो अपनी आईलैशेज को ब्यूटीफुल दिखा सकती हैं, लेकिन वे वास्तव में वैसी नहीं होती हैं। जिस तरह ब्यूटीफुल स्किन पाने के लिए आप उसका ख्याल रखती हैं। ठीक उसी तरह, लंबी व घनी आईलैशेज पाने के लिए आपको उसकी भी केयर करनी पड़ती है। हालांकि, इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही आईलैश जेल बनाएं और उसे इस्तेमाल करके घनी आईलैशेज पाएं-

नारियल तेल और एलोवेरा जेल

नारियल तेल और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके आईलैश जेल तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप नारियल तेल और एलोवेरा जेल को बराबर मात्रा में लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप एक साफ मस्कारा वैंड लें और उसकी मदद से तैयार मिश्रण को अपनी पलकों पर लगाएं। नियमित रूप से ऐसा करने से आपको जल्द ही असर नजर आने लगेगा।

कैस्टर ऑयल और विटामिन ई जेल

अगर आप अपनी आईलैशेज की ग्रोथ को बेहतर बनाना चाहती हैं तो आपको कैस्टर ऑयल और विटामिन ई की मदद से जेल बनाना चाहिए। इसके लिए आप कैस्टर ऑयल में विटामिन ई तेल की कुछ बूंदें मिक्स करें। सोने से पहले इस मिश्रण को अपनी पलकों पर लगाने के लिए मस्कारा वैंड की मदद लें। इससे ना केवल आईलैश की ग्रोथ अच्छी होती है, बल्कि यह उन्हें टूटने से भी बचा सकता है।

अलसी के बीज और विटामिन ई जेल

अलसी के बीज और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन आईलैशेज के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले 1/4 कप अलसी के बीज को 3 कप पानी में उबालें। धीमी आंच पर इसे 10 से 15 मिनट तक उबालें। इससे अलसी के बीज की जेल जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब आप तैयार जेल को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। अब, इस जेल का 1 बड़ा चम्मच लें और इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल तोड़ डालें। अच्छी तरह मिक्स करके साफ मस्कारा ट्यूब में डालें। रात को सोने से पहले इसे अपनी आईलैशेज पर लगाएं।

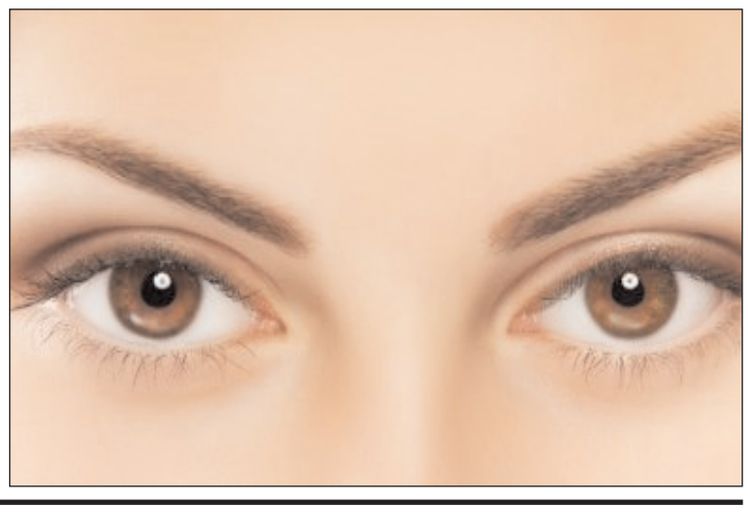

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

चरण सिंह, स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव को भारत रत्न

नईदिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और बड़े कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों नाम की घोषणा की है। चौधरी चरण सिंह को जहां किसानों का बड़ा नेता माना जाता है। वह समाजवादी नेता रहे हैं। वहीं, एमएस स्वामीनाथन कृषि क्रांति के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को साधने के लिए मोदी सरकार का यह बड़ा दांव माना जा सकता है। इसके अलावा दक्षिण से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित कर केंद्र ने यह भी बताने की कोशिश की है कि वह सभी को साथ लेकर चलती है। दिलचस्प बात यह भी है कि पीवी नरसिम्हा राव से पहले केंद्र की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया था।

भाजपा और जयंत चौधरी के बीच पक्की हुई डील!

लखनऊ। विपक्षी इंडिया गुट को एक और झटका देते हुए, जयंत चौधरी की आरएलडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन पर लगभग बात बन गई है। सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार, आरएलडी दो लोकसभा सीटों, बागपत और बिजनौर पर चुनाव लड़ेगी, और एक राज्यसभा सीट का भी वादा किया गया है। गठबंधन की औपचारिक घोषणा अगले दो-तीन दिनों में कर दी जायेगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक के घटकों के बीच सीट-बंटवारे को लेकर मतभेद के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। रालोद ने अपने नेताओं के बयान देने पर पाबंदी लगा दी है। खबर है कि इसकी औपचारिक घोषणा 15 या 16 फरवरी को भी हो सकती है। इसका बड़ा कारण राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। दरअसल, यह यात्रा आगामी 16 फरवरी को चंदौली के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। यह यात्रा उत्तर प्रदेश में करीब 11 दिन रहेगी और लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी।

लैंड फॉर जॉबः मीसा, हेमा और राबड़ी देवी कोर्ट में हुईं पेश

पटना। लैंड फॉर जॉब मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती, हेमा यादव समेत कई अन्य आरोपियों की पेशी हुई। अदालत ने शुक्रवार को भूमि घोटाले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। कोर्ट ने ईडी से चार्जशीट पर जबाव मांगा है। पेशी के बाद दोनों बेटियों के साथ राबड़ी देवी एक ही गाड़ी पर घर के लिए निकल गयी। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए राबड़ी, मीसा भारती समेत 9 लोगों को 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। जिस पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान जेल में बंद दो आरोपी वीसी के माध्यम से पेश हुए।

तीन राज्यों में उम्मीदवारों के लिए 13 को बैठक करेगी 'आप'

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) गुजरात, हरियाणा और गोवा के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय करने के वास्ते 13 फरवरी को अपनी राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक करेगी। पार्टी के एक सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) में साझेदार कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर वार्ता के लंबे समय तक खिंचने से नाराजगी का संकेत देते हुए 'आप' ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुवाहाटी समेत असम की तीन सीट के लिए बृहस्पतिवार को अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। सूत्र ने कहा, गुजरात, गोवा और हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी की पीएसी 13 फरवरी को बैठक करेगी। 'आप' के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक ने डिब्रूगढ़ से पार्टी उम्मीदवार मनोज धनोहर, गुवाहाटी से भावेन चौधरी और सोनितपुर से ऋषि राज के नाम की घोषणा की थी।

बाबा सिद्दीकी जल्द ही राकांपा में शामिल होंगे : अजित पवार

पुणे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख अजित पवार ने पूर्व कांग्रेसी नेता बाबा सिद्दीकी द्वारा गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कहा कि वो जल्द ही एनसीपी में शामिल होंगे। इसके साथ ही पवार ने यह भी कहा कि रविवार को कुछ और बड़े नेता एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। मीडिया के अनुसार शुक्रवार को पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, बाबा सिद्दीकी 10 फरवरी की शाम को एनसीपी में शामिल होंगे और 11 फरवरी को कुछ और लोग पार्टी में शामिल होंगे। बीते गुरुवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी ने कहा, मुझे निर्णय लेना था और मैंने निर्णय ले लिया है। जब आपको कोई बात समझ में न आए और बार-बार कहे जाने पर भी उसमें सुधार न हो तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि अब आपकी जरूरत नहीं है और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए तो मैं आगे बढ़ गया हूं।

श्वेत पत्र पर बहस : मोदी सरकार ने 'राष्ट्र प्रथम' रखकर संकट की स्थिति से देश को निकाला- सीतारमण

कांग्रेस ने देश को नहीं 'प्रथम परिवार' को आगे रखा इसलिए अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में पहुंची : वित्तमंत्री

नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर सच्ची गंभीरता, पारदर्शिता से और राष्ट्र को प्रथम रखकर काम हो तो परिणाम सकारात्मक होते हैं, वहीं यदि देश को प्रथम नहीं रखकर 'प्रथम परिवार' को सामने रखा जाए तो भयावह संकट की स्थिति पैदा होती है। वित्त मंत्री ने 'भारतीय अर्थव्यवस्था और देश के नागरिकों पर इसके प्रभाव पर श्वेतपत्र' को लोकसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करते हुए ये बातें कहीं। सदन में नियम 342 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई।

आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन और तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने श्वेतपत्र के विरोध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए। सीतारमण ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में श्वेतपत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के 10 साल और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 10 साल की अर्थव्यवस्था की तुलना की गई है। सीतारमण ने आज कहा कि दुनिया की पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से भारत के पांच शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचने और तीन शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के करीब पहुंचने के तथ्यों को इस श्वेतपत्र में पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ रखा गया है।

उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के रिकॉर्ड में भविष्य के लिए ये तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए, जो पूरे देश, सभी युवाओं के काम आएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब शासन संभाला तब अर्थव्यवस्था संकट में थी। उन्होंने कहा कि इस श्वेतपत्र में बताया गया है कि किस तरह प्रधानमंत्री ने दूरदृष्टि के साथ देश को सम्मान दिलाने के लिए पिछले 10 साल में किस तरह काम किया।

उन्होंने कहा, ''यह श्वेतपत्र स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर सच्ची गंभीरता, पारदर्शिता से और 'राष्ट्र को प्रथम' रखकर सरकार काम करती है तो परिणाम कितने सकारात्मक होते हैं। और यदि आप देश को प्रथम नहीं रखते, पहले परिवार को सामने रखते हैं, पारदर्शिता के बजाय कुछ और प्राथमिकताएं रखते हैं तो परिणाम कैसे होते हैं।'' उन्होंने कहा कि 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी से ज्यादा बुरे हालात कोविड-19 महामारी के समय थे, लेकिन सरकार की नीति और नीयत साफ थी तो अच्छे परिणाम मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को कैसे संभाला, किस तरह पूरे देश को टीके मुफ्त में उपलब्ध कराए और देश को बचाया, यह सब कैसे हुआ? इसका ब्योरा इस गंभीर दस्तावेज में है।

उन्होंने कहा कि संप्रग के समय 'राष्ट्रमंडल खेल घोटाले' में जहां पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई, वहीं जी-20 में समस्त राज्यों में आयोजनों के साथ विदेश में देश का सम्मान बढ़ा।

सीतारमण ने कहा कि संप्रग के दौरान कोयला खनन घोटाले से देश का बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण नौकरियों में नुकसान हुआ, निवेश नहीं आया और सहायक लघु उद्योग पूरी तरह ठप पड़े और बिजली उत्पादन के लिए कोयला आयात करना पड़ा। उन्होंने कहा, ''ये तो सत्यानाश करके चले गए। हमने सुधारात्मक उपाय किए, कोयला खनन विशेष प्रावधान कानून बनाया और जिला खनन कोष स्थापित किया। इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत एफडीआई आना शुरू किया। अब कोयला खदान नीलामी से आवंटित की जाती हैं, पिछले दरवाजे से नहीं।''

वित्त मंत्री ने कहा, ''ये (कांग्रेस) लोग हमें क्रॉनी कैपिटलिज्म पर ज्ञान देते हैं। इन्होंने कोयले को राख बना दिया। हमने अपनी नीतियों के तप से कोयले को हीरा बना दिया।'' उन्होंने कहा कि इस साल देश में 90 करोड़ टन कोयला उत्पादन हुआ है जो सर्वाधिक है और अगले वर्ष एक अरब टन कोयला उत्पादन का पूर्वानुमान है।

चर्चा करते समय किसी संस्थान का नाम न लें : ओम बिरला

नई दिल्ली। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को सदन के सदस्यों को किसी भी मुद्दे को उठाते समय किसी विशेष संस्था या संगठन का नाम न लेने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को केवल नीतिगत मामलों पर चर्चा करनी चाहिए। उनका यह बयान उस वक्त आया जब सदन की कार्यवाही के दौरान उत्तर प्रदेश बसपा सांसद रितेश पांडे ने एक मेडिकल कॉलेज और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मान्यता के लिए इसके आवेदन का मुद्दा उठाया था। सदन में सदस्यों से अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं आप सभी से अपील करता हूं कि किसी भी मुद्दे को उठाते समय किसी भी संस्थान का नाम ना लें। अगर आप लागातार ऐसा करेंगे तो इसका संसदीय प्रक्रियाओं पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। आप नीतिगत मुद्दों को उठात सकते हैं, जो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन किसी का नाम सही नहीं है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी भी चिकित्सा पाठ्यक्रम को मान्यता देने पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है।

राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का प्रधानमंत्री पर निशाना

मोदी को तो बिना सड़कों पर आंदोलन किए मिला ओबीसी वर्ग का दर्जा : खड़गे

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर राजनीति तेज हो गई है। गुरुवार को राहुल गांधी ने सबसे पहले मोदी की जाति पर सवाल उठाए। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी राहुल का समर्थन करते हुए मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। खरगे ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी को बिना सड़कों पर आंदोलन करे ओबीसी वर्ग का दर्जा मिला है, जबकि देश में करोड़ों लोग ओबीसी लिस्ट में खुद को शामिल करवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

अपने लंबे एक्स पोस्ट में खड़गे ने कहा कि आजकल पूरे देश को मोदी जी सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ा रहें हैं। उनकी जाति को तो ओबीसी दर्जा मिल गया। वो अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी भी कहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी को तो बिना सड़कों पर आंदोलन करे ओबीसी वर्ग का दर्जा मिल गया, पर देश में करोड़ों लोग ओबीसी लिस्ट में अपने आप को शामिल कराने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहें हैं। उन्होंने कहा कि देश की कई सारी ऐसी पिछड़ी जातियां हैं, जो मोदी जी के जाति जनगणना के विरोध के चलते, अन्य पिछड़ा वर्ग दर्जा नहीं ले पाएंगी। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात में लाखों लोग कई वर्षों से अपनी जाति को ओबीसी का दर्जा दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरें हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी में विश्वगुरु तो मोदी जी बन गए! पर ये नहीं बता रहे कि जातिगत जनगणना - जाति जनगणना कब होगा? सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए जातिगत जनगणना - जाति जनगणना सबसे ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि हम जाति जनगणना ज़रूर करवाएंगे! राहुल ने कहा कि वह अपने पूरे जीवन में जातीय जनगणना नहीं होने देंगे क्योंकि उनका जन्म ओबीसी में नहीं, सामान्य जाति में हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सामान्य वर्ग में पैदा हुए और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति ओबीसी में बदल दी।

मोदी ने किया था वार

मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने ओबीसी के साथ अन्याय किया है, उसने अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले दिनों कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिये जाने की घोषणा की जिन्हें 1987 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार करने से कांग्रेस ने मना कर दिया और कारण बताया कि वह संविधान का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग चिंता जताते हैं कि मोदी सरकार में कितने पदों पर ओबीसी के लोग बैठे हैं। मोदी ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, ''उन्हें सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। कहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं।'' उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के समय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद नाम से एक निकाय बनाया गया था, कांग्रेस देखकर बताए कि क्या उसमें एक भी पदाधिकारी ओबीसी से था।

खेल
प्रमुख समाचार

अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया

नईदिल्ली। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 सीजन अब फाइनल में एंट्री कर चुका है। ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका की मेजबानी में खेला जा रहा है। वहीं इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया 11 फरवरी को बेनोनी में टकराएंगे।

भारतीय टीम ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका टीम 2 विकेट से हराया था। तो पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त देकर कंगारू टीम फाइनल में जगह बना पाई है। लेकिन बता दें कि अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 2 बार टक्कर हुई है। दोनों ही बार भारत ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की है। दोनों टीमों के बीच फाइनल में तीसरी बार टक्कर होगी।

अगर भारतीय टीम जीतती है तो ये उसकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में जीत की हैट्रिक होगी। इससे पहले भारतीय टीम वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2012 और 2018 में भी हरा चुकी है। पिछला वर्ल्ड कप 2022 खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता था।

इसके साथ ही भारतीय टीम अब तक सबसे ज्यादा 5 बार अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर चुकी है। जबकि 3 बार उसे फाइनल में हार मिली है। इस तरह भारतीय टीम अब 9वीं बार फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम ने ये वर्ल्ड कप खिताब 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 सीजन जीता है।

जबकि दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 बार खिताब अपने नाम किया है। उसने ये खिताब 1998, 2002 और 2010 सीजन में जीते हैं। उसे फाइनल में दो बार हार का सामना करना पड़ा। ये दोनों ही बार भारतीय टीम ने कंगारूओं को शिकस्त दी थी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 167 अंक चढ़ा निफ्टी 21,783 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में मिलेजुले रुख के बीच उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को दो दिन से जारी गिरावट के बाद हरे निशान में बंद हुआ। इंडेक्स में हैवी वेटेज रखने वाले बैंकिंग शेयरों में खरीदारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा आईटीसी के शेयरों में तेजी के चलते बाजार चढ़कर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज मामूली गिरावट लेते हुए अपने पिछले बंद भाव के 71,428.43 मुकाबले 71,410.29 पर खुला। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 71,676.49 के हाई और 71,200.31 के लॉ लेवल तक झूलने के बाद 0.23त्न या 167.06 अंक चढ़कर 71,595.49 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 0.3 प्रतिशत या 64.55 अंक चढ़ने के बाद 21,782.50 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में स्टेट बैंक का शेयर सबसे ज्यादा 3.55 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ।

पेटीएम के शेयर में गिरावट लग सकता है लोअर सर्किट

नईदिल्ली। पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को भी लुढ़क गए हैं। यह गिरावट लगातार दूसरे दिन देखने को मिली है। बीएसई पर कंपनी का शेयर 8.67 प्रतिशत की गिरावट के साथ 408.30 रुपये पर आ गया। अगर कंपनी का शेयर 10 फीसदी तक टूट गया तो इसमें एक बार फिर से लोअर सर्किट लग जाएगा। बीएसई और एनएसई ने पेटीएम के शेयर के लिए सर्किट लिमिट को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर कंपनी का शेयर में 8.20 प्रतिशत गिरकर 410 रुपये पर रहा। बता दें कि तीन सत्र की भारी गिरावट के बाद गत मंगलवार को शेयर में तेजी आई थी। लेकिन वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर में गुरुवार को 10 प्रतिशत की गिरावट फिर से आ गई।

यस बैंक के शेयरों ने पिछले एक महीने 30 प्रतिशत चढ़ा

नईदिल्ली। यस बैंक लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 9 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर लगभग चार साल के हाई लेवल पर पहुंच गए। बैंक के शेयरों में यह तेजी दरअसल एसबीआई के एक बयान के बाद आई है। इस बयान में एसबीआई ने कहा है कि उसकी यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचने की कोई योजना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के शेयरों में पिछले चार दिनों से उछाल आ रहा है। इससे पहले मंगलवार को एचडीएफसी बैंक को यस बैंक समेत छह बैंकों में 9.5 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से नियामक मंजूरी मिल गई। इसके बाद से बैंक के शेयरों में तेजी जारी है। बीएसई पर उपलब्ध शेयरधारकों के आंकड़ों के अनुसार, एसबीआई की यस बैंक में 26.13 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि एचडीएफसी बैंक की निजी ऋणदाता में 3 फीसदी हिस्सेदारी है।

एमआरएफ का तीसरी तिमाही में मुनाफा तीन गुना बढ़ा

नईदिल्ली। टायर निर्माता एमआरएफ ने शुक्रवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 509.71 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की इसी तिमाही की तुलना में तीन गुना अधिक है। बता दें कि कंपनी का पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में शुद्ध लाभ 174.83 करोड़ रुपये था। एमआरएफ ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में एकीकृत शुद्ध लाभ बढ़कर 1,685.12 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 428.29 करोड़ रुपये था। नियामक फाइलिंग के अनुसार, वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू साल-दर-साल आधार पर 9.3 प्रतिशत बढ़कर 6,047.8 करोड़ रुपये हो गया।

कहीं उम्मीदें ज्यादा तो नहीं, पेटीएम और बायजू संकट से उठते हैं कुछ सवाल

गुलाम अहमद

बीते 31 जनवरी को स्टार्ट-अप दुनिया में भारत के सबसे मशहूर नामों में से एक पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आदेश के बाद पेटीएम संदेह के घेरे में आ गया है। इससे न केवल पहले से ही घाटे में चल रहे पेटीएम बैंक की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बल्कि शेयर बाजार में भी इसके शेयरों में निरंतर उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।

हालांकि पेटीएम बैंक के खिलाफ केंद्रीय बैंक की यह पहली कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह मार्च, 2022 से ही चल रहा था, जब पेटीएम बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोकने के लिए कहा गया था और इसके खिलाफ एक व्यापक ऑडिट शुरू किया गया था। अक्तूबर, 2023 में आरबीआई ने %अपने ग्राहक को जानें% (केवाईसी) मानदंडों का अनुपालन नहीं करने के कारण पेटीएम बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया था। नवीनतम कार्रवाई में अनिवार्य रूप से पेटीएम बैंक की बैंकिंग गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि पेटीएम यूपीआई ऐप जिसकी वजह से कंपनी ने पहली बार शोहरत हासिल की थी, फिलहाल चालू रहेगा।

पेटीएम की यह पूरी कहानी दरअसल स्टार्ट-अप की दुनिया की हकीकतों को सामने लाती है। स्टार्ट-अप की दुनिया में दरअसल वैश्विक अर्थव्यवस्था की दो अलग-अलग प्रवृत्तियां साथ दिखती हैं। इसमें एक ओर तो एक नए तरह के 'निवेशकों', वेंचर पूंजीपतियों या एंजेल इन्वेस्टर्स के एक वर्ग का उदय हुआ, जो उन लोगों की श्रेणी में थे, जो मूल रूप से उद्यमों के मुनाफे में हिस्सेदारी के बजाय उनमें अपने

निवेश के मूल्य में वृद्धि से मुनाफा कमाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे उस उद्यम के शेयर खरीदकर फंड उपलब्ध कराते हैं और इन शेयरों के मूल्य में वैसे ही वृद्धि से लाभ की उम्मीद करते हैं, जैसे शेयर बाजार के कारोबार में करते हैं। ये %मूल्य% जो उद्यम की दीर्घकालिक कमाई की संभावनाओं पर आधारित होते हैं, प्रकृति में पूरी तरह से सट्टा जैसे होते हैं और वास्तव में अर्जित मुनाफे के बजाय व्यवसाय के विकास की संभावनाओं से जुड़े होते हैं। इन्हीं संभावनाओं के चलते इतने सारे स्टार्ट-अप को विकास के लिए फंडिंग मिलती रहती है, भले ही वर्षों तक वे मुनाफा न कमाएं। निवेशक भी अपने जोखिम को कम करने के लिए निवेश को कई उद्यमों के बीच वितरित करके उनमें विविधता लाते हैं।

दूसरी प्रवृत्ति डिजिटल प्रौद्योगिकी का उदय है, जो हमारे काम करने के तरीके को बदल रही है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, दुकान पर जाकर खरीदारी करने की जगह ले रहा है, ऐप के माध्यम से कैब बुक हो रही है या भोजन मंगाया जा रहा है और इन सब के लिए डिजिटल साधनों से भुगतान भी किया जा रहा है। वास्तव में कोई भी नया उद्यम स्टार्ट-अप है, लेकिन आजकल जिसे स्टार्ट-अप कहा जाता है, वे डिजिटल प्रौद्योगिकी पर आधारित वैसे नए व्यवसाय हैं, जो सट्टे की तर्ज पर काम कर रहे निवेशकों द्वारा वित्त पोषित होते हैं।

पेटीएम बैंक भी पारंपरिक बैंकों के साथ निजी बैंकों के एक विशेष वर्ग को बढ़ावा देने की रिजर्व बैंक की एक खास पहल का नतीजा था, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना था। हालांकि इन बैंकों को छोटी जमा राशि स्वीकार करने और ग्राहकों को भुगतान व पैसे भेजने की सुविधा देने की अनुमति थी, लेकिन कर्ज देने की अनुमति नहीं थी। लेकिन यह पहल वास्तव में कभी सफल नहीं हो सकी। वर्ष 2015 में जिन 11 संस्थानों को सैद्धांतिक रूप से पेमेंट बैंक स्थापित करने की अनुमति दी गई, उनमें से मात्र छह ही चालू हैं। इसलिए पेमेंट बैंक की व्यवहार्यता हमेशा से ही एक मुद्दा रही है।

हालांकि पेटीएम पेमेंट बैंक प्रकरण की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिवाय इसके कि रिजर्व बैंक ने अपनी कार्रवाई के व्यापक कारणों को सार्वजनिक किया है, और वे अनिवार्य रूप से प्रणालीगत नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा कर रहे हैं।

जहाँ सच हैं,वहाँ पर हम खड़े हैं... इसी खातिर आँखों में गड़े हैं...

भाजपा के कभी पितृ पुरुष कहलाने वाले भाजपा के पूर्व अध्यक्ष,पूर्व डिप्टीपीएम लालकृष्ण आडवाणी पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके, राष्ट्रपति भी नहीं बन सके पर उम्र के अंतिम पड़ाव में भारतरत्न से सम्मानित होने जा रहे हैं। उन्हे संतोष हो सकता है कि अभिन्न रहे अटलजी को यह सर्वोच्च सम्मान मिला और उन्हें भी..... लालकृष्ण आडवाणी नाम का एक ऐसा शख्स। जिसने अपने खून-पसीने कोतराजू पर रख,अपनी उम्र को नीलाम कर दिया, लेकिन पीएम की कुर्सी की बेवफाई ने उन्हें उम्र भर तरसाया..! राजनेता आडवाणी ने सन 1951 से अपने सियासी जीवन की शुरुआत की। कभी पार्टी के सूत्रधार होने का गौरव मिला,तो कभी लौह पुरुष का सम्मान...। कभी देश की पहली गैर कांग्रेसी सत्ता में मंत्री भी रहे,तो वहीं भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक...कभी रथयात्रा के कर्णधार बने,तो कभी पार्टी के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए,कभी कद इतना बड़ा हुआ कि गिरफ्तार भी हुए, तो वह भी सम्मान से।फिर बाहर भीआए,तो आन- बान और शान से। वह तो उस जमाने के थे,ज़ब लोग मोहब्बत का ककहरा पढ़ रहे थे।शायद किस्मत को ही,कुर्सी से मोहब्बत रास नहीं आ रही थी। कभी किस्मत ने भी,ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया कि उनके और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच कुछ कदमों का ही फैसला रह गया।2004 में जब पार्टी अपने पूरे शबाब पर भी हार गई।उसके ऊपर अटलजी का राजनीति से सन्यास.. तब ऐसा लगा कि अब प्रधानमंत्री की कुर्सी उनसे बहुत दूर नहीं है? 2009 में गमों ने और 2014 में नमो (नरेंद्र मोदी)ने झटका दिया..। राजनेता आडवाणी को कुछ ऐसा तोड़ा कि फिर जुड़ पाना मुमकिन नहीं था। जो भी हो, मार्गदर्शक मंडल में जुड़ पाना उनका कद ही तो है,बेशक सबसे बड़ा। नाराजगी है, तो उस कुर्सी से। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पैट्रिक स्कूल कराची में हुई, उनकी सामा जिक यात्रा 1947 से शुरू मानी जाती है। मात्र15 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य के रूप में कार्य शुरू किया। डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1951में,जब जनसंघ की स्थापना की, तब शुरुआत के 6 वर्षों तक सचिव रहे। फिर 1973 से 1977 तक जनसंघ के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया।बाद में 1980 को भाजपा की स्थापना हुई, तब 1986 तक वे पार्टी के महासचिव रहे।

इसके बाद अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्वभी संभाला आडवाणी ने,1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राममंदिर आंदोलन के लिये एक रथ यात्रा भी निकाली, लेकिन उन्हें बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी लोकप्रियता, कद और भी बड़ा हो गया,बाद में 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस में भी उनका नाम शामिल रहा। आडवाणी तीन बार अध्यक्ष पद पर भी शोभायमान रह चुके हैं।चार बार राज्य सभा,पाँच बार लोकसभा के भी सदस्य रहे।पहली बार पार्टी के सत्ता मेंआने पर, वह सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे, अपने राजनीतिक जीवन में उप प्रधानमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं।

पीएससी के पूर्व अध्यक्ष, अन्य के खिलाफ जुर्म कायम

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता,भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। इस प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराये जाने के राज्य सरकार के निर्णय के परिपालन में ही आर्थिक अपराध अन्वेषण द्वारा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों के विरूद्ध अपराधपंजीबद्ध कर लिया गया है। राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया था, छग लोक सेवाआयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2021 जो 170 पदों के लिए ली गई थी,जिसके परिणाम 11 मई 2021 को जारी किए जाने के पश्चात् लोक सेवा आयोग पर अनियमितता, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ननकीराम कंवर व अन्य के माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायती पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि तब के अध्यक्ष टामन सिंह, सचिव जीवनकिशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक एवं शासन तथा आयोग में तत्समय पदस्थ संलिप्त लोक सेवकगण, संबंधित राजनेतागण एवं अन्य द्वाराअपने-अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आयोग की चयन प्रक्रिया वर्ष 2020 एवं 2021 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा में नियम विरूद्ध तरीके से षड़यंत्र करते हुये अपने पुत्र,पुत्री व रिश्तेदारों को पात्र योग्य अभ्यार्थियों के बदले इनका चयन पदों पर करते हुए शासन एवं उन योग्य अभ्यार्थियों के साथ भ्रष्ट आचरण करते हुये छलकारित किया गया है,जो कि धारा 120 बी, 420, भादवि एवं धारा 7, 7 (क), एवं 12 भ्र.नि.अ. 1998 यथा संशो. 2018 के तहत अपराध कारित किया जाना पाया गया है,अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

आईपीएस राहुल भगत बने सीएम के सचिव....

आईपीएस राहुल भगत छग सीएम के सचिव बनाए गए हैं। राहुल राजनांदगांव रेंज के आईजी पद पर पदस्थ थे,2005 बैच के आईपीएस हैं,वे पहले भी विष्णुदेव साय के साथ काम कर चुके हैं। केंद्रीय इस्पात एवं खान,श्रम रोजगार राज्यमंत्री जुब साय थे तब राहुल को प्रतिनियुक्ति में केंद्र में ले गये थे। बाद में उन्हें भारत सरकार ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में डायरेक्टर बनाया था, इस पद पर आईएएस की नियुक्ति होती थी। बेहद साफ सुथरी छवि के राहुल भगत नारायणपुर, कांकेर, रायगढ़, कवर्धा के एसपी रह चुके हैं। भगत स्पेशल टास्क फोर्स के एसपी भी रहे हैं।

अमित के बाद अमरेश की भी छग वापसी....

केंद्रीय जाँच एजेंसी सीबीआई में संयुक्त सचिव रहे आईपीएस अमित कुमार की छग वापसी, खुफ़िया चीफ बनाने के बाद अब छग कैडर के आईपीएस अमरेश मिश्र छग लौट कर आईजी रायपुर का पदभार सम्हाल चुके हैं।अमरेश 2005 के आईपीएस हैं।अमरेश एनआईए में डीआईजी के पद पर पदस्थ रहे।अमरेश दंतेवाड़ा,कोरबा,दुर्ग तथा रायपुर के एसपी रह चुके हैं।

चर्चित आईपीएस पुलिस मुख्यालय में...

छग की विष्णुदेव सरकार ने कई आइपीएस का नाम कोयला, महादेव सट्टेबाजी एप में आने, ईडी की रडार में आने पर उन्हें पुलिस मुख्यालय भेजा है। बिलासपुर आइजी रहे अजय यादव, रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, डा.आनंद छाबड़ा, बद्री नारायण मीणा,आरिफ शेख ,पारुल माथुर को पीएचक्यू भेजा गया है वहीं दीपांशु काबरा की सेवा परिवहन विभाग से वापस लेकर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। सभी के नाम किसी न किसी मामले में चर्चा में रहे थे। आईपीएस की तबादला सूची में बिलासपुर के आईजी संजीव शुक्ला, संतोष सिंह को रायपुर का एसपी (अभी तक लगातार 9 जिले के एसपी) बनाया गया है,वहीं विजय अग्रवाल को सरगुजा, रजनीश सिंह को बिलासपुर का एसपी बनाया गया है। कई एसपी भी बदले गये हैं।

और अब बस.....

- पामगढ़ से कॉंग्रेस की पहली बार एमएलए बनी श्रीमती शेषराज हरबंस का कोरबा में राखड़ समस्या पर ध्यानाकर्षण स्वीकृत हो गया था,यह बात और है कि बहिष्कार के चलते इस पर चर्चा नहीं हो सकी...
- एक बुद्धिजीवी द्वारा भोजनालय खोलने की तैयारी की भी जमकर चर्चा है।

मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला बजटः उप मुख्यमंत्री शर्मा

रायपुर। आज छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मोदी की गारंटी को पूरा करने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा आज घोषित किया गया यह बजट एकमात्र आय-व्यय का सिर्फ लेखा-जोखा नही बल्कि यह बजट छत्तीसगढ़ की उन्नति का बजट है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में जनता से कोई नए कर का प्रावधान नही किया गया है, आज के बजट में किसी कर के दर में वृद्धि किये बैगर बजट का आकार बढ़ना सच मे चमत्कार है। हमारी सरकार द्वारा लीकेज रोककर और टेक्नोलॉजी उपयोग करके बजट के आकार को बढ़ाया गया है। हमारे प्रदेश के लिए यह बहुत ही अच्छा बजट है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हरेक आयाम को छूता हुआ और विशेष रूप से मोदी जी की गारंटी को पूरा करता हुआ यह बजट है। बजट रुपये के लेखा जोखा का बजट नही होता, यह भविष्य का आधारशिला होता है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2028 तक जीएसडीपी को 10 लाख करोड़ रखने का। यह बजट छत्तीसगढ़ के उन्नति का आधारशिला है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और हमारी सरकार के पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि इस बजट में गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार आने वाले एक साल में कई महत्वपूर्ण कार्य करेगी इसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,369 करोड़, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिये 2,788 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 561 करोड़, ग्राम पंचायत में बिजली भुगतान के लिए अनुदान 500 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 94 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़,स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़, पीएम जन-मन योजना के लिए 300 करोड़ के लिए प्रावधान किया गया है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रूपए के छत्तीसगढ़ के अमृत काल के नींव का बजट पेश किया। यह बजट GYAN अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की समृद्धि और पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने और राज्य के युवाओं को रोजगार एवं आजीविका बढ़ाने पर केन्द्रित है। यह बजट मोदी की गारंटी के तहत वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

किसानों, गरीबों, पिछड़ी जातियों सहित वर्गों के लिए कल्याणकारी बजटः नेताम

रायपुर। कृषि और आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव सरकार का प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के किसानों, गरीबों, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक सहित सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी बजट है। राज्य सरकार की मजबूत बजट प्रावधान और कल्याणकारी नीतियों से युवाओं, महिलाओं तथा कमजोर वर्गों में समृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नए रास्ते खुलेंगे। मंत्री श्री नेताम ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट पेश किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। यह सरकार की प्रदेश और लोगों के विकास की दृढ़ इच्छा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं सहित गरीब व जरूरतमंद परिवारों के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गारंटियों को भी पूरा करने का प्रावधान रखा गया है। यह सरकार की नियत और नीति को परिलक्षित करता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने बस्तर और सरगुजा के लोगों के निरंतर विकास के लिए संकल्पित हैं यहां के लोगों को मल्टीसिटी शहरों की तरह एयर कनेक्टिविटी मिले और ईकों टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। निश्चित ही इससे आदिवासी अंचल के लोगों के विकास के लिए नए रास्ते खोलेंगे। मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कहा कि भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसम्बर सुशासन दिवस के अवसर पर संकल्प पत्र में किए गए वादा को पूरा करते हुए राज्य के 12 लाख से अधिक किसानों को 3 हजार 716 करोड़ रूपए के बकाया धान बोनस की राशि का भूगतान करने का काम किया। वहीं राज्य सरकार अपने वादा को पूरा करते हुए किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी और प्रति क्विंटल 3100 रूपए की भाव से धान खरीदकर नया कीर्तिमान बनाया है। राज्य सरकार किसानों को समर्थन मूल्य के बाद अंतर की राशि प्रदान करने कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है, जल्द ही किसानों को अंतर की राशि मिलेगी। इसके अलावा बजट प्रावधान में आदिवासी अंचल के तेंदूपत्ता संग्रहकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रति मानक बोरा 4000 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया गया है। यह दूरस्थ आदिवासी अंचलो के गरीबो, महिलाओं के हित में एक बड़ा कदम है। साथ ही प्रदेश के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के जरिए 10 हजार रूपए वार्षिक देने का प्रावधान गरीबो के विकास में सहायक सिद्ध होगी। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि हमारी सरकार अनूसुचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग एवं कमजोर वर्गो के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए आश्रम-छात्रावासों संचालित कर रही है। इन वर्गो के बच्चें जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंक, रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली में स्थित 65 सीटर यूथ हॉस्टल को 200 सीटर किए जाने का प्रावधान इन वर्गो के बच्चों के विकास के लिए नए रास्ते खोलेंगे।

प्रमुख समाचार
छत्तीसगढ़/राजधानी

नया अध्याय लिखेगा यह बजटः लखनलाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अथक ऊर्जा और सरल सहज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा आज घोषित किया गया यह बजट एकमात्र आय-व्यय का सिर्फ लेखा-जोखा नही बल्कि 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग तक लाभ पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वित्त मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के अमृतकाल के नींव का बजट आज विधानसभा में पेश किया गया। मोदी जी के 2047 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस बजट में उद्योग और श्रम के क्षेत्र में प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार आने वाले एक साल में कई महत्वपूर्ण कार्य करेगी इसका लाभ हजारों मजदूरों को मिलेगा। नई उद्योग नीति जल्द ही लागू की जायेगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की जाएगी। इससे प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 हजार की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। असंगठित श्रमिकों, असंगठित सफाई कर्मकारों, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं हमालों के कल्याण के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना प्रारंभ होगी।

जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने और मोदी की गारंटी पूरा करने वाला बजट

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट राज्य की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला तथा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने दो महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। इस बजट के जरिए छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के साथ कदम ताल मिला कर चलेगा। यह 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के सपना को पंख देने वाला बजट है। हमारी सरकार की नजरिया विकास है। जिसमें गरीबों, नौजवानों, किसानों और महिलाओं का बहुमुखी विकास हो। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी सड़क सभी के लिए प्राप्त व्यवस्था की गई है। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी बेहतर प्रावधान है। पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय, नई बिल्डिंग खोलने के लिए, नए स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग में पारदर्शिता के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षक और कर्मचारियों की उपस्थिति और व्यय आदि दूसरी जानकारी दर्ज की जाएगी।

राशन कार्ड नवीनीकरण में बालोद जिला पहले स्थान पर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 09 फरवरी की स्थिति में 48 लाख 80 हजार 829 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले स्थान पर बालोद जिला में कुल 2 लाख 21 हजार 810 हितग्राहियों में से 1 लाख 81 हजार 892 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। इसी प्रकार पर द्वितीय स्थान पर कांकेर जिले में कुल 1 लाख 87 हजार 999 हितग्राहियों में से 1 लाख 45 हजार 57 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है और तीसरे स्थान पर धमतरी जिले में कुल 2 लाख 42 हजार 320 हितग्राहियों में से 1 लाख 85 हजार 585 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है.

कोंडागांव के राजेश विदेश में निभाएंगे भारतीय राजदूत की जिम्मेदारी

रायपुर। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तेहान होता है, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लडने वालों के कदमों में जहां होता है। ये लाइन छत्तीसगढ़ के एक पिछड़े इलाके से निकलकर विदेश में भारतीय राजदूत बनने तक का सफर तय करने वाले राजेश उइके पर बिलकुल सटीक बैठती हैं। कोंडागांव जिले से आने वाले उइके ने असुविधाओं को पार कर सफलता की प्रेरणादायक कहानी लिखी है। 2006 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी उइके की हाल ही में ताजिकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति हुई है। ताजिकिस्तान के लिए निकलने से पहले उइके ने बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने ताजिकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में आधिकारिक नियुक्ति को चिह्नित करते हुए उइके को क्रेडेंशियल दस्तावेज प्रस्तुत किए। वर्तमान में, राजेश उइके नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के बाहरी प्रचार एवं सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके राजनयिक करियर में विदेशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में विभिन्न भूमिकाएं, साथ ही नई दिल्ली में मंत्रालय के भीतर विभिन्न जिम्मेदारियां शामिल हैं।

महतारी वंदन को लेकर बजट में भाजपा की बदनीयती सामने आई

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बजट से भाजपा की बदनीयती सामने आई है। मोदी की गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों को एक बार फिर छला गया। इस बजट में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पूरे 1 वर्ष के लिए कुल बजट प्रावधान मात्र 3000 करोड़ रूपया अर्थात ढाई सौ करोड़ रूपए महीना? प्रदेश में कुल महिला मतदाताओं की संख्या लगभग एक करोड चार लाख है, भारतीय जनता पार्टी के साय सरकार के द्वारा किए गए बजट प्रावधान से मात्र 25 लाख महिलाओं को ही 1000 रुपया महीना दिया जा सकेगा, अर्थात भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार की मंशा प्रदेश के लगभग 80 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना से बाहर रखने का है। बजट के अनुसार तो 25 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रूपया महिना मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से साय सरकार षडयंत्र पूर्वक शर्तें लाद रही है। उससे लगता है कि 20 प्रतिशत महिलाओं को भी लाभ देने की इनकी नीयत नहीं है। शुक्ला ने कहा कि बजट से साफ साय सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि नहीं। विष्णुदेव सरकार का पहला बजट जनता को निराश करने वाला है। इस बजट से राज्य की प्रगति के मार्ग में बाधा पैदा होगी।

नया भवन लगभग 12 करोड़ रूपए की लागत से बन कर होगा तैयार

मुख्य न्यायाधिपति सिन्हा ने नवीन न्यायालय भवन का किया वर्चुअल भूमिपूजन

रायपुर। ज़िला मुख्यालय बेमेतरा में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की और बेहतर सुविधा और न्याय प्रणाली में तेजी लाने के लिए आज मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर श्री रमेश कुमार सिन्हा ने नवीन भवन का वर्चुअल भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। उनकी वर्चुअल उपस्थिति एवं अनुमति से कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि न्यायाधिपति श्री गौतम भादुड़ी ने भूमिपूजन एवं शिलालेख का अनावरण किया।

यह नवीन न्यायालय भवन कलेक्ट्रेट के पास निर्मित होगा। भवन के लिये 7.04 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। भूमि पूजन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधिपति श्री गौतम भादुड़ी, जो कि जिला न्यायालय बेमेतरा के पोर्टफोलियों न्यायाधीश है, विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर ज़िला न्यायाधीश श्री बृजेंद्र शास्त्री, कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री प्रणिश चौबे सहित अधिवक्ता,न्यायालय के कर्मचारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्य कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण श्री निर्मल सिंह ने इस नवीन भवन निर्माण की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि तक़रीबन 12 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित होगा। निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा यह राशि स्वीकृत कर दी गयी है। नवीन जिला न्यायालय भवन में अधिवक्ता कक्ष, शासकीय अभिभाषक कार्यालय आदि भवन का निर्माण कार्य किया जायेगा। यह भवन कलेक्ट्रेट के समीप 15 महीने में बनकर तैयार होगा। न्यायाधिपति श्री गौतम भादुड़ी ने कहा कि नये भवन बन जाने से अधिकारी-कर्मचारियों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश जब यहां आये तो नये न्यायालय भवन की उन्होंने आवश्यकता महसूस की और कहा कि जल्द ही भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। आप लोग देख सकते है नये भवन का जो नक्शा है वह बहुत ही सुन्दर है। कोई भी निर्माण कार्य एक दिन में नहीं बनती है। इसे बनने में काफी समय लगता है सालों-साल लग जाते है, पर यहां मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा के प्रयास से आज ये शुभ दिन आया। उन्होंने इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया।

जन अपेक्षाओं के विपरीत, झूठे सपने और खोखले दावों का घोर निराशाजनक बजट - बैज

रायपुर। छत्तीसगढ़ बजट 2024 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि साय सरकार का पहला बजट आम जनता के अपेक्षा और उम्मीदों के विपरीत घोर निराशाजनक रहा है, ना इसमें युवाओं के रोजगार के संदर्भ में कोई रोड मैप दिख रहा है, ना ही महंगाई से निपटने कोई ठोस रणनीति है। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा था, लेकिन बजट में नई नौकरियों के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं, उल्टे बेरोजगारी भत्ता की राशि खा गए। कॉलेज जाने वाले छात्रों से वादा था यात्रा भत्ता देने का जिसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा करने वाले भाजपाई गैस सब्सिडी के लिए एक रुपए का भी बजट प्रावधान नहीं कर पाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बजट 1 साल के लिए होता है, लेकिन झांसा 2047 तक का? छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत आज का बजट अभिभाषण पूरी तरह से भाजपा के चुनावी जुमलो की तरह ही था। झूठ और लफ्फाजी के कसीदे पढ़े गए। मोदी की चरण वंदना में समर्पित इस बजट में छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्र सरकार की अपेक्षा और भेदभाव का कोई जिक्र नहीं था। केंद्रीय करों में रोके गए राज्य की हिस्सेदारी और कोल की रायल्टी के पेनल्टी का पैसा वर्षों से लंबित है उस पर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। बैज ने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रस्तुत पिछले बजट में छत्तीसगढ़ में चार-चार नए मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था दी गई थी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.